हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

17 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 17 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7) 21
सदस्यों को लैपटॉपस इत्यादि देने बारे में सूचना	(7) 30
वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(7) 30

मूल्य : 210

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 17 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात:10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवरपाल) ने अध्यक्षता की।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Blue Revolution to Develop Fisheries

***341 Smt. Prem Lata** : Will the Fisheries Minister be pleased to state—

a) whether there is any proposal under consideration of Government to launch Blue Revolution to develop fisheries in the State ; and

b) if so, the details thereof together with the Fish production in the State during the last four years?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

क. श्रीमान, राज्य में अंतर्देशीय मछली पालन के विकास के लिए विभाग में योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

ख. राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान मत्स्य उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त किये गये लक्ष्य (मि0टन0 में)
1	2010-11	93950
2	2011-12	106000.00
3	2012-13	111480.00
4	2013-14	105579.50

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

मत्स्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य योजना स्कीमों का विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	प्राप्तियां	बजट प्रावधान (रुपये लाखों में)	खर्च(रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	**सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम**	-	-	143.00	94.11
	मत्स्य पालन के अधीन जलक्षेत्र	19215.00 हैक्टेयर	12435.75	-	-
	मत्स्य बीज संचय	4850.00 लाख	4055.00	-	-
	मत्स्य उत्पादन	114000.00 टनों में	75166.90	-	-
2	**राष्ट्रीय मत्स्य बीज कार्यक्रम**	-	-	105.75	90.39
	मत्स्य बीज उत्पादन	-	-	-	-
	i. राजकीय क्षेत्र	1150.00 लाख	503.97	-	-
	ii. निजी क्षेत्र	5000.00 लाख	3995.50	-	-
3	**बहते पानी में मत्स्य विकास**	-	-	10.00	8.66
	मत्स्य उत्पादन	4060.00 टनों में	2994.50	-	-
4	**कृषि मानव संसाधन विकास**	-	-	36.50	25.58
	प्रशिक्षण	1110 संख्या	646	-	-
	तालाबों की मिट्टी तथा पानी के नमूनों की जांच	1000 संख्या	726	-	-
5	**सजावटी मछली पालन की हैचरी**	-	-	7.00	5.29
	मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण	50 संख्या	-	-	-
	रियरिंग ईकाई	25 संख्या	-	-	-
6	**मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों की भलाई के लिए योजना**	-	-	42.00	39.78
	तालाबों की प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर सहायता	100.00 हैक्टेयर	121.42	-	-
	जालों की खरीद पर अनुदान	300 संख्या	235	-	-
	अधिसूचित पानी में मछली पकड़ने के ठेके पर अनुदान	4 संख्या	3	-	-
	मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण	420 संख्या	380	-	-
7	**कैपिटल आउट-ले**	-	-	25.00	-

मत्स्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	प्राप्तियां	बजट प्रावधान (रुपये लाखों में)	खर्च (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	**ताजा पानी में जल कृषि विकास (एफ.एफ.डी.ए.)**	"	-	252.00	130.00
	क) मत्स्य पालन के अधीन जलक्षेत्र	2400.00 हैक्टेयर	1785.89	"	-
	ख) नये तालाबों का निर्माण हैक्टेयर	123.00	49.57	-	-
	ग) मत्स्य उत्पादन टनों में	14160.00	10210.40	"	-
2	**जलमग्न क्षेत्रों में जल कृषि का विकास**	"	-	6.00	"
	नये जल क्षेत्र का विकास	8.00 हैक्टेयर	10.00	-	-
	जलकृषि के अधीन जलक्षेत्र	210.00 हैक्टेयर	126.70	-	-
	मत्स्य उत्पादन	1240.00 टनों में	678.00	"	-
3	**भूमिगत खारे पानी का मत्स्य पालन के उपयोग**	"	-	9.00	"
	नये जल क्षेत्र का विकास	10.00 हेक्टेयर	10.00	-	"
	जलकृषि के अधीन जलक्षेत्र	175.00 हैक्टेयर	124.30	"	-
	मत्स्य उत्पादन	1032.00 टनों में	613.60	"	-
4	**अन्तर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय/नदियां)**	"	-	12.00	5.28
	क्राफट एवं गियर (जाल, नौकाएं आदि)	400 संख्या	82	"	-
5	**राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड**	"	"	20.00	-
	मत्स्य किसानों का प्रशिक्षण	200 संख्या	-	-	"
	किसान मेला/Exposure यात्रा	1 संख्या	"	"	-
	तालाबों का सुधार	100.00 हेक्टेयर	20.60	-	"
6	**मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार**	-	"	25.00	-
7	**मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नेटवर्किंग डेटाबेस और सूचना का सुदृढ़ीकरण**	"	-	21.04	4.13

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि राज्य में मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए नीली क्रान्ति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा गत 4 वर्षों के दौरान राज्य में मछली उत्पादन कितना है ? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में वर्ष 2010-2011 में 93950 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन शुरू करके वर्ष 2013-2014 तक राज्य में 105579 मिलियन टन उत्पादन पहुंचा है। अभी माननीय सदस्या की जो मंशा है क्योंकि किसान को मत्स्य पालन से आमदनी बहुत होती है और मत्स्य पालन के लिए बाजार भी ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। मत्स्य पालन के लिए हरियाणा में जितनी मात्रा में विस्तार होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है। कुछ लोग इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के अच्छे काम से जिस प्रकार से पूरे स्टेट के किसानों को इससे लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इससे जिस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए वह अभी नहीं हो पाया है। जिस मुकाम तक किसानों को इस मत्स्य पालन के लिए पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचे हैं। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (R.A.S.) के अण्डर एक सुल्तान सिंह नामक किसान को एक इण्डस्ट्रियल मछली उत्पादन के प्रोजैक्ट के लिए सैन्ट्रल ऐड मिली है। उस किसान का बजट 45 करोड़ रूपये का है जिसमें से 18 करोड़ रूपये की सैन्ट्रल ऐड उसे भारत सरकार से मिलेगी। इस मामले में एक केन्द्रीय सरकार की स्कीम हमें मिली है। मत्स्य पालन का काम धीरे धीरे शनैःशनैः करके राज्य में बढ़ रहा है। पंजाब के बाद देश में मत्स्य उत्पादन में हरियाणा का दूसरा नम्बर है। पंजाब प्रति हैक्टेयर 6100 किलोग्राम मत्स्य उत्पादन करता है जबकि हरियाणा में 5900 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जाता है जबकि देश का औसत उत्पादन 2900 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर का है। लेकिन निश्चित रूप से विभाग इस प्रकार की योजनाएं बना रहा है। बहुत छोटे बजट का यह मंत्रालय है। आज वित्त मंत्री जी सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। हमने इस काम के लिए वित्त मंत्री जी से और बजट बढ़ाने की मांग की है।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, तीन तरह की रेवोल्यूशन होती हैं। एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो कृषि से संबंधित है, दूसरी व्हाईट रेवोल्यूशन जो दूध से संबंधित और तीसरी ब्ल्यू रेवोल्यूशन जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या हरियाणा राज्य में मछली पालन के लिए कोई सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है ? दूसरा हम जो मछली का सीड तैयार करते हैं क्या हमारे राज्य में मछली के सीड के बारे में कोई शोध किया गया है ? मुझे दिल्ली में पुसा से पता चला है कि मछली पालन के लिए हाल ही में कोई रिसर्च किया गया है कि वेस्ट वाटर को अगर ट्रीट किया जाए तो उस पानी में मछली का पालन किया जा सकता है और उस पानी में मछलियों के लिए 20-30 प्रतिशत् फीड ही डालनी पड़ती है, 100 प्रतिशत् फीड नहीं डालनी पड़ती है। इस प्रकार से मछली ज्यादा क्वानटिटी में तैयार होती हैं। जब मछली का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वास्तव में किसानों को भी फायदा होगा। इस विषय में Indian Council for Agriculture Research ने शोध किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे कृपया बतायेंगे कि हरियाणा में भी कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध है अथवा नहीं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा में मीठे पानी और खारे पानी में भी मछली-पालन का काम हो रहा है तथा ओरनामैंटल वाले विषय में भी हम आगे

बढ़ रहे हैं। एक नई जानकारी मुझे मिली है, जो शायद विभाग के अधिकारियों को भी हो, वह यह है कि खारे पानी को किसी तरह से कुछ लैवल पर स्वच्छ करके सदुपयोग किया जा सकता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मत्स्य-पालन वाले किसानों को, अपने मछली-उत्पादन की बिक्री के लिए तथा बाजार ढूंढने के लिए व तालाब बनाने से लेकर मोटर साईकिल खरीदने आदि पर सरकार की तरफ से सब्सिडीज़ की सुविधा उपलब्ध हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगले महीने मेरे ख्याल से 20 किसानों के एक समूह को हम ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रहे हैं तथा इस नई जानकारी का भी हम लाभ उठायेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह सरकार फिश-फार्मज़ को बढ़ावा दे रही है, सरकार की यह बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर गाँवों में जो तालाब होते हैं लगभग सभी ग्राम पंचायतें उनको मछली-पालन के लिए ठेके पर देती है तथा उन्हीं तालाबों के अंदर गाँव के पशु भी पानी पीते हैं। देखने में यह आया है कि कई बार पानी गंदा होने की वजह से या किसी अन्य बीमारी के कारण सारी मछलियाँ मर जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या विभाग ने ऐसा कोई प्रबंध किया है कि तालाब में विशेषकर मछलियाँ मर जाने से पानी दूषित न हो सके ? चूंकि ये तालाब किसानों को ठेके पर दिये जाते हैं जिसका रिकार्ड विभाग के पास होता है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या विभाग समय-समय पर उस पानी की सैम्पलिंग करवाता है या भविष्य में इस दूषित पानी की सैम्पलिंग करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में विकास एवं पंचायत मंत्री होने के नाते मेरे पास भी यह प्रश्न आया हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट का जो सिस्टम है, वह हमारे यहां बहुत अच्छी तरह से विकसित हो गया है तथा सारे तालाबों का एक लैवल सैट हो गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो शुरूआत है तथा निश्चित रूप से आने वाले समय में, जैसे स्वच्छता का अभियान चला है ऐसे ही हम 3-टैंक वाले सिस्टम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हरियाणा में एक गांव में औसतन 3 या 4 जोहड़ होते हैं। लेकिन जब से यह नल-सिस्टम आया है उसके बाद पशुओं के लिए उपयोग होने वाले जोहड़ कम हो गये हैं। परिणामस्वरूप जो पानी वेस्टेज में जा रहा है उसका कोई ट्रीटमैंट नहीं है तथा इस प्रकार से जोहड़ खत्म हो रहे हैं। इस तरह से तीनों तरीकों से पानी के उपयोग करने की एक संयुक्त योजना कृषि मंत्रालय, विकास एवं पंचायत विभाग और शहरी विभाग ने बैठकर शुरू की है कि हम कुछ जोहड़ों का उपयोग रिचार्जिंग के लिए, आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए तथा फिशरीज़ उत्पादन के लिए करें। गाँवों में ड्रेनेज सिस्टम को भी सुचारू बनाया जायेगा क्योंकि एक ही जोहड़ में सारा पानी नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरीके से लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट का सिस्टम लागू करेंगे तथा एक-आध जोहड़ गांव में पशुओं के पीने के पानी के लिए रखेंगे। इस बारे में मैं एकदम सही जानकारी तो अभी सदन में नहीं दे सकता, पूरी जानकारी तो मैं अभी अर्जित करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सभी चीजों का बीमा होता है वैसे ही मछली-पालन हेतु भी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होगी, यदि नहीं भी होगी तो विभाग उसकी व्यवस्था करने के लिए कदम आगे बढ़ायेगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हरियाणा राज्य में खारे पानी में

[श्री नसीम अहमद]

भी मछली-पालन की नई स्कीम लागू की गई है जिसके तहत झींगा मछली को खासतौर से पाला जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खारे पानी में जो यह मछली-पालन किया जा रहा है क्या यह हरियाणा में कामयाब है, यदि कामयाब है तो अब तक इससे कितना उत्पादन हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि यह स्कीम बहुत कामयाब हो रही है लेकिन इस समय पूरे आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं इसलिए मैं माननीय साथी को ये आंकड़ें भिजवा दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि फिशिंग का प्रोडैक्शन स्टेट में हो और इसका एक्सपोर्ट हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार मछली खाने पर पाबंदी लगाने का मन रखती है क्योंकि मछली की पूजा होती है और मछली को देवी देवता की तरह पूजा जाता है इसलिए ये अगर मछली खाने पर पाबंदी लगाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह इनकी पार्टी का मुद्दा है और हिन्दू धर्म की इनकी पार्टी है इसलिए क्या इस पर विचार किया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक चुटकला सुनाना चाहता हूं। (विघ्न) एक गांव में ठेका न खुले और शराबबंदी हो इसके लिए पंचायत हो रही थी और ठेके वाले भी पंचायत में जाकर बैठ गए कि इस बैठक को कामयाब नहीं होने देना। जब विषय शुरू हुआ कि ठेका नहीं खुलना चाहिए तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बिल्कुल ठीक है लेकिन मुद्दे कुछ और भी हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि जब भी गांव में बारात आती है तो हम पेठा बनाकर खड़े हो जाते हैं, आगे से शाही पनीर बनना चाहिए क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल है। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा कि अक्सर हम देखते हैं कि शादी में भाती बड़ी देर से आते हैं इसलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि भाती गांव के हो जाएं (हंसी)और पंचायत पलट गई। कल सर्वसम्मति से अपनी आस्थाओं के आधार पर इतना अच्छा विधेयक हमने पारित किया। दलाल साहब, तो हिच लगा रहे हैं। हमारी स्टेट वैजीटेरियन स्टेट है और उसके हिसाब से मत्स्य पालन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि लोग इस प्रकार के व्यवसाय में अधिक से अधिक आएं क्योंकि यही एकमात्र प्रोडैक्ट है जिसके लिए हमको बाजार को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, बाजार अभी हमारे पास आ रहा है। हर प्रोडैक्ट के लिए किसान को दिक्कत आती है कि वह अपने प्रोडैक्ट को बेचने के लिए कहां जाए और कहां अपने प्रोडैक्ट को बेच कर लाभ उठाए। दिल्ली जैसे एन.सी.आर. का इतना बड़ा बाजार हमारे पास उपलब्ध है और इसका लाभ हमें अधिक से अधिक उठाना चाहिए।

To Develop Park

***350. Sh. Kulwant Ram Bazigar :** Will the Development and Panchay at Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in Sewan of Guhla Cheeka Constituency?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सीवन में एक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का पार्क विकसित करने की अभी कोई प्रपोजल नहीं है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत कोई भी ग्राम पंचायत अपनी जमीन पर पार्क विकसित करना चाहती है तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, वे पार्क विकसित कर सकते हैं। बहुत से गांवों में इस प्रकार के पार्क विकसित हुए हैं।

श्री कुलवंत राम बाजीगर : अध्यक्ष महोदय, सीवन मेरे हल्के का बहुत बड़ा कस्बा है। यह सब तहसील भी है और पिछली सरकार ने इसको आदर्श गांव भी बनाया था लेकिन इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है इसलिए पार्क तो जरूर होना चाहिए। इस गांव में 35-40 हजार की आबादी है इसलिए पार्क का होना बहुत जरूरी है। पानी की निकासी के बारे में मैंने पहले भी प्रश्न लगाया था तथा और भी बहुत से काम हमारे यहां होने वाले हैं जिनकी पिछली सरकार ने अनदेखी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां एक पार्क जरूर विकसित करवाया जाए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, जिस गांव का मुद्दा इन्होंने उठाया है उस गांव में शामलात भूमि 34 एकड़ 6 कैनाल और 13 मरला है। इसमें 9 एकड़ 6 कैनाल और 13 मरला चारान भूमि है और 25 एकड़ भूमि ग्राम पंचायत ने पट्टे पर दे रखी है। यह जो इनकी जमीन है गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है इसलिए इतनी दूर पर पार्क बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। गांव की 4 एकड़ भूमि जो गांव के नजदीक है उसमें तालाब बना हुआ है जिसको बनाए रखना जरूरी है और उसको बंद नहीं किया जा सकता। गांव के नजदीक किसी भूमि के बारे में विभाग ने पता भी किया है और सोचा है कि आपको सूचित करें कि आप वहां पार्क बना सकते हैं लेकिन उसके बाद भी यदि कोई और प्रपोजल भूमि एक्सचेंज वगैरह की आती है तो उसमें विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कुलवंत राम बाजीगर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां बी.डी.पी.ओ. आफिस के सामने 6 एकड़ जमीन है जो कि गांव के बीच में पड़ती है। जिसमें से 2 एकड़ जमीन पुलिस थाना बनाने के लिए दे दी गई है और 4 एकड़ जमीन अभी बाकी है। वहां पर पुलिस थाना भी बनेगा और पंचायत वहां जमीन देने के लिए प्रस्ताव भी पास करके भेज देगी इसलिए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां बी.डी.पी.ओ. आफिस के सामने पार्क बनाने की कृपा करें ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके भेजती है और ऐसी कोई जमीन उपलब्ध है जो पार्क बनाने के लिए वाजिब हो तो वहां पार्क बनाने में हमें कोई एतराज नहीं है।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पार्क पहले से ही विकसित हैं क्या उनको सुरक्षित रखने की सरकार की कोई योजना है ? यदि ऐसा है तो मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के रतिया में कारगिल शहीद श्री देवेन्द्र के नाम पर 4 साल पहले जमीन का डिमार्केशन पार्क बनाने के लिए किया गया था और उस जगीन की बाउंडरी भी कर दी गई थी। उस समय एस.डी.एम.

[प्रो. रविन्द्र बलियाला]

श्री पांडूरंगा जी थे ? लेकिन कोई शरारती तत्व उस जमीन का फेक रजिस्ट्रेशन करवाकर हड़पना चाहता है। क्या मंत्री जी इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि जो पहले ही पार्क विकसित हो रखे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जो पार्क विकसित हैं उनकी देख रेख पंचायतें करती हैं। जैसा माननीय साथी ने पार्क की जमीन हड़पने की बात की है इस बारे में पूरी जानकारी माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें। जमीन हड़पने वालों के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मंत्री जी हमारे शहर के और हमारे ही वार्ड के रहने वाले हैं। इसी तरह से कमल गुप्ता जी भी हमारे ही शहर के और हमारे ही वार्ड के रहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नाते मंत्री जी की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि दादरी में पार्क विकसित किए जायें। दादरी में 50 साल पहले एक पार्क बना था। वहां 50 साल के दौरान जनसंख्या बहुत बढ़ी है यह बात मंत्री जी भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दादरी शहर में 2-3 नये पार्क विकसित किए जायें। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि बींद कला बहुत बड़ा कस्बा है और उप तहसील भी है। वहां की करीबन 40 हजार की आबादी है क्या वहां सरकार द्वारा कोई पार्क विकसित करने की योजना है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय साथी ने दादरी शहर में पार्क विकसित करने की बात की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अर्बन लोकल बॉडीज का महकमा मेरे पास नहीं हैं। भाई राजदीप जी, कमल गुप्ता जी और मैं हम तीनों एक ही मौहल्ले के हैं। हम निश्चिंत रूप से दादरी में पार्क बनवाने के लिए बात करेंगे। जहां तक माननीय साथी ने बींद कला में पार्क विकसित करने की बात की है। इस बारे में यदि पंचायत की तरफ से कोई प्रपोजल आता है तो उसको हम आगे बढ़ायेंगे।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ गांवों में जगह की बहुत कमी है और वहां पर तालाब पानी से भरे होते हैं। उन गांवों में ड्रेन बनाकर नजदीक के किसी नाले में पानी निकासी का इंतजाम करके क्या उस जगह को पार्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का सुझाव अच्छा है। जिन गांवों के आस पास ड्रेन हैं और वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है तो उस जगह का उपयोग भी किया जा सकता है। अभी तो जहां पर ड्रेन दूर हैं वहां के लिए लिक्विड वेस्ड मैनेजमैंट के तहत 3 टैंक पॉलिसी, 4 टैंक पॉलिसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं ।

Construction of PHC Building

*363 **Shri Kuldip Sharma :** Will the Health Minister be pleased to state :-

a) whether it is a fact that the PHC of village Ahulana in Ganaur Constituency is functioning in the Sub Health Centre at present;and

b) if so, the time by which building of abovesaid PHC is likely to be constructed for which land has already been given by the Gram Panchayat of Ahulana?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) आवश्यक स्वीकृतियां उपरान्त, निर्माण प्रारंभ होने की तिथि से लगभग दो वर्ष लगेंगे।

Shri Kuldeep Sharma: Speaker Sir, although, I am not fully satisfied with the answer given by the Hon'ble Minister because he has not fixed up a date. Nobody knows when the necessary approval will be given by the concerned department. First, he should clarify when the necessary approval will be granted and actually when the construction will be started?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आज लगा देखकर मैं बहुत आहत हुआ हूं जिस व्यक्ति ने सरकार को बचाने के लिए अपना सारा कैरियर दांव पर लगा दिया वह व्यक्ति अपने गांव में 10 साल के दौरान एक डिस्पैंसरी भी नहीं बनवा सका। अहुलाना इनका अपना गांव है और इस आहुलाना गांव में ये डिसपैंसरी नहीं बनवा सके। हालांकि इन्होंनें इस गांव के लिए डिसपैंसरी को सैंक्शन करवा लिया था लेकिन डिसपैंसरी बनाने के लिए सरकार की कुछ गाईडलाईन्स होती हैं। सबसे पहले तो इसके लिए सरकार को ज़मीन देनी पड़ती है और उस ज़मीन को सरकार के नाम ट्रांसफर करवाना पड़ता है। इस गांव की पंचायत ने इस बारे में रेजोल्यूशन पास कर दिया लेकिन आज तक भी इस ज़मीन को सरकार के नाम नहीं करवाया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक वह ज़मीन ही सरकार के नाम ट्रांसफर नहीं होती है तब तक कार्यवाही होना संभव नहीं है। जिस तिथि की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं हम वह तिथि घोषित नहीं कर सकते। जब यह ज़मीन ट्रांसफर हो जायेगी उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें इस काम को करने में कितना समय लगेगा और कब तक यह डिसपैंसरी बनकर तैयार हो सकती है।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, through you, I want to ask the Hon'ble Health Minister that he should know difference between Dispensary and PHC. PHC is already functional there in Sub-Centre. Only construction of new building has to be taken place, for which the Hon'ble Health Minister commits that it will take about two years from the date of commencement of construction after taking necessary approvals. I just wanted to know when the necessary approval of the Gram Panchayat is there as Gram Panchayat has already handed over resolution to the concerned department. Now, he should also to see when the Panchayat gave resolution in favour of construction of PHC, necessary approval by the Revenue Department such as mutation in the name of Government and concerned department to take place. I mean to say that it was done three months ago after I became legislator. I was no longer in my home town. Secondly, Sir, there is also one related issue. I brought it to the notice of the Hon'ble Health Minister

[Shri Kuldip Sharma]

personally. About two months ago, I had gone to the CHC, Ganaur at about 09.00 A.M. for my personal check-up as I was not feeling well. When I went there, I was informed that Doctor is in the Doctors' Duty Room. When I went in the Doctors' Duty Room, I found that the Doctor present is smoking and couple of stuff lying all over there and there were two bottles of Cough Syrup for intoxicate purpose which he had consumed half bottle. I brought this matter to the notice of the Hon'ble Minister. This was also reported in the News Channels as well as in the Newspapers. Hon'ble Minister goes everywhere in the State to see how Hospitals are functioning but I want to ask the Hon'ble Minister what action has been taken in the matter which I brought to his notice.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह डिसपैंसरी सब-सैंटर में चल रही है और नैसैसरी स्टॉफ भी वहां पर सारे का सारा लगा हुआ है। जहां तक इस पी.एच.सी. के लिए नया भवन बनाने का सवाल है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस पी.एच.सी. के लिए जो नया भवन बनाना है उसके लिए पंचायत ने 29 कनाल और 13 मरला भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया है लेकिन अभी तक यह ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। हमने इस पी.एच.सी. की बिल्डिंग के एस्टीमेट्स भी बनवा लिये हैं और इसका साईट प्लॉन भी तैयार करवा लिया है जैसे ही यह ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर होगी हम बजट की उपलब्धता को देखते हुए इसको बनाने पर विचार करेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने दूसरी बात बताई कि वहां पर कोई डॉक्टर स्मोकिंग कर रहा था। स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि इन्होंने यह बात मुझे बताई थी। एक दिन जब इनको हरियाणा भवन, नई दिल्ली में कमरा नहीं मिला था और ये वापिस जा रहे थे तो उस दिन ये हरियाणा भवन, नई दिल्ली लॉन में मुझे मिले थे। स्पीकर सर, यह भी वक्त-वक्त की बात है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज जी, जब कुलदीप शर्मा जी को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में कमरा नहीं मिला था तो क्या आपने इनको कमरा दिलवा दिया था?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको कमरा दिलवाने की बात कही थी लेकिन इन्होंने यह कहा था कि मैं आपकी कृपा से कमरा नहीं लेना चाहता। सर, यह तो वक्त-वक्त की बात है एक समय वह भी था जब हरियाणा भवन, नई दिल्ली में हमें कमरा नहीं मिलता था और आज इनको नहीं मिलता। Sir, I am truly speaking जैसा कि मैं समय-समय पर प्रदेश के अलग-अलग हॉस्पिटल्ज़ में जाता हूं और किसी भी प्रकार की कोताही और अनियमितता पाये जाने पर मैं on the spot कार्यवाही करता हूं। मैंने यह चाहा था कि मैं गन्नौर के हॉस्पिटल में भी जाऊँ और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये माननीय सदस्य वहां पर रिमार्कस लिखकर आये हैं तो वहां जाकर उन रिमार्कस के ऊपर कार्यवाही करूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। यह मेरे कैरेक्टर में शुमार है। अगर मैंने किसी को बख्श दिया तो मेरा कैरेक्टर खराब हो जायेगा। I assured him on the floor of the House that inquiry will be conducted and strict action will be taken against that doctor.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के गांव मोहाना में एक पी.एच.सी. बननी है, उसकी बिल्डिंग बहुत खराब हालत में है। वहाँ पर स्टाफ तो तैनात कर दिया है लेकिन

बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। पंचायत ने रैजोल्यूशन पास करके जमीन भी ट्रांस्फर कर दी है, उसके लिए केवल बजट देना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगले बजट में इस पी.एच.सी. के लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह एक सैप्रेट प्रश्न है। अभी तो बजट ही पेश नहीं हुआ, अभी तो मुझे ही नहीं पता कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। बजट में इसका प्रावधान होगा या नहीं यह मैं कैसे बता सकता हूँ ?

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी विधान सभा क्षेत्र में निगदू गांव में पी.एच.सी. के लिए ग्राम पंचायत ने जमीन ट्रांस्फर कर दी है लेकिन उसके बाद उस पर और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

Construction of Barrage on Yamuna in Palwal District

*3. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Barrage on Yamuna passing through Palwal/Faridabad districts in near future; and

b) if so, the name of the villages where Barrage will be constructed togetherwith details of amount to be spent on the Project ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड) :

(क) & (ख) नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई परियोजना अभी तक विचाराधीन नहीं है क्योंकि हरियाणा राज्य को पानी ओखला बैराज से आगरा नहर और गुड़गांव नहर द्वारा मिल रहा है और इन दोनों नहरों द्वारा फरीदाबाद व पलवल जिलों को सारा साल पानी यमुना नदी के द्वारा दिया जाता है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि यमुना नदी पर यह बांध बनाना केवल पलवल और फरीदाबाद जिले के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यमुना के किनारे पर रेनीवैल स्कीम के तहत जो बोर किये गये हैं उनसे मेवात में जो पानी पहुंचता है, अब उस भूजल का स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। जो यमुना नदी का पानी है वह सारा का सारा समुद्र में जाता है उस पानी की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार वहाँ पर बांध बना देती है तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो धरती का जल स्तर ऊपर आ जायेगा और मेवात तक के लोगों को जो पीने का पानी मिल रहा है उसमें कमी नहीं आयेगी। दूसरी बात यह है कि यमुना का जो पानी समुद्र तक जाता है और उस पर किसी का कोई हक नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर ये वहाँ पर बांध बना

[श्री करण सिंह दलाल]

देते हैं तो लिफ्ट इरीगेशन से उस पानी को पूरे पलवल जिले में और मेवात तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार हमारी जरूरतों को देखते हुए यमुना नदी पर बैराज बनाने के बारे में पुन: विचार करेगी ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पानी की रिचार्जिंग और उसके उपयोग के लिए बहुत अच्छी बात दलाल जी ने कही है लेकिन अभी यमुना नदी में जो पानी आता है वह नवम्बर से फरवरी तक 1138 क्यूसिक, मार्च से जून तक 1338 क्यूसिक और जुलाई से अक्तूबर में ज्यादा होता है जो कि 8560 क्यूसिक होता है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीनों का हिस्सा है। उसमें नवम्बर से फरवरी तक हमारा हिस्सा 600 क्यूसिक है और मार्च से जून 700 क्यूसिक है और बाद में फिर जुलाई से अक्तूबर 600 क्यूसिक है। हमारी यह पानी की मात्रा औखला बैराज से बांट कर हमको दी जाती है। मुझे लगता है कि जैसे यह इश्यू महत्वपूर्ण है उससे भी महत्वपूर्ण एक और इश्यू भी है। करण दलाल जी उसमें सहयोग करें, सरकार भी उसमें लगेगी, यह सारा का सारा कैनाल सिस्टम उत्तर प्रदेश का है। एक समय ऐसा आया था कि उत्तर प्रदेश को आबियाना नहीं दिया जाए यह फैसला किया गया था और उसके बाद लोगों ने आबियाना नहीं दिया था। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का 14 करोड़ का आबियाना अभी बकाया है। उसी कारण से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय कर लिया है कि कब कितना पानी देना है और अब वे पानी अपनी मर्जी से देते हैं इसलिए आज पानी की मात्रा के अधिकार की लड़ाई है। अगर इस कैनाल सिस्टम से हमको 850 क्यूसिक पानी का हक बनता है वह हमें मिलना चाहिए लेकिन अभी तक तो केवल 150 से 500 क्यूसिक पानी ही भिन्न-भिन्न समय पर हरियाणा को प्राप्त हो रहा है। उस इलाके में पानी का पूरा मालिक उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करके इस कैनाल सिस्टम का पानी उस इलाके के लिए हम ले सकें तो अच्छा होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इच्छा जताई है कि एक बार उत्तरप्रदेश के संबंधित मंत्री स्तर पर इस वार्ता को आगे बढ़ाएं ताकि इस विषय को निपटाकर पलवल व फरीदाबाद के किसानों को अधिक से अधिक पानी मिल सके। इसके अलावा भी इस विषय से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण ईश्यूज हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उसकी भी वाथबिलिटी पर विचार करेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह बहुत अच्छी बात है। आबियाना वाला जो मुद्दा है उसको तो हम इनके साथ बैठकर फिर कभी निपटा लेंगे क्योंकि उसके मुद्दे दूसरे हैं। आज जो यमुना के ऊपर बैराज बांध बनाने की बात है, ज्यों ही हमारे पलवल जिला की सीमा खत्म होती है उसके बाद मथुरा जिला शुरू होता है और वहां पर गोकुल है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यू.पी. गवर्नमैंट ने यमुना के ऊपर गोकुल में बैराज बनाया हुआ है और उससे उन्हें पानी का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारा जो हिस्सा यमुना के अन्दर है हमें उस पानी के हिस्से का झगड़ा नहीं है। हमारा निवेदन केवल यह है कि जब गोकुल में यू.पी. सरकार हमसे 15 किलोमीटर आगे बैराज बना सकती है तो क्या हमारी सरकार मेवात और पलवल के लोगों को पीने का पानी दिलवाने के लिए और धरती का जो जल स्तर नीचे खिसक रहा है उसे ठीक करने के लिए पलवल में बैराज बनाने पर विचार नहीं कर सकती ?

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जोकि दलाल साहब ने कहा कि पलवल व मेवात जिले की तो भारी समस्या है ही, अगर ये बैराज बनता है तो जो पीने का पानी है वह फरीदाबाद शहर के लिए भी और गुड़गांव शहर के लिए भी वह बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। सर, जो एक्सैस पानी है वह वैसे ही बह कर चला जाता है मुख्य बात तो उस पानी को रोकने की है। जैसे कि गोकुल में बैराज को रोका गया है। जहां तक मंत्री जी कह रहे हैं कि उस आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के माध्यम से सारा साल पानी मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होडल रजबाहे की कैपेसिटी 200 क्यूसिक पानी है और उसके पानी की जो एवेलेबिलिटी है वह फरवरी महीने में बिल्कुल निल है। उसमें एक दिन भी पानी नहीं चला। जनवरी महीने में सिर्फ एक दिन 104 क्यूसिक पानी मिला। दिसम्बर महीने में सिर्फ सात दिन 394 क्यूसिक पानी मिला। नवम्बर महीने में सिर्फ इक्कीस दिन 1477 क्यूसिक पानी मिला। 16800 क्यूसिक पानी जो हमें मिलना चाहिए था उसके एगेंस्ट सिर्फ 1975 क्यूसिक पानी मिला। उसी तरह से जो हसनपुर रजबाहा है उसमें भी फरवरी महीने में सिर्फ सात दिन 667 क्यूसिक पानी मिला। जनवरी महीने में सिर्फ छः दिन 356 क्यूसिक पानी मिला। दिसम्बर महीने में सिर्फ आठ दिन 610 क्यूसिक पानी मिला। नवम्बर महीने में सिर्फ सात दिन 647 क्यूसिक पानी मिला। जहां 21 दिन पानी मिलना चाहिए वहां सात दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन है नहीं। हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि पलवल, मेवात और फरीदाबाद जिले को हरियाणा का कौन सा हिस्सा मानते हैं। उत्तर वाले इसको उत्तर का हिस्सा नहीं मानते और दक्षिण वाले इसको दक्षिण का हिस्सा नहीं मानते। पश्चिम वाले तो इनको अपना हिस्सा मानते ही नहीं। हमने तो यह भी कह दिया कि पूर्व ही मान लो। सर, हमारी यह बहुत भारी समस्या है। अभी जो आबियाने की बात कर रहे हैं वह हरियाणा से सारे डिफर है अर्थात बिल्कुल अलग है। उनके ढाई गुना रेट हैं आबियाने के जिसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी बात हरियाणा में पक्की माईनर बनी हुई है लेकिन हमारी माइनर सारी कच्ची हैं और पूरी तरह से यू.पी. पर निर्भर हैं। क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उस पर मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूं। फिर से इन्होंने इसको एडर्स किया है। इसमें से 11 रजबाहे हैं सबकी क्यूसिक क्षमता भी मेरे पास है लेकिन मैंने कहा कि दिल्ली में जितना भी कैनाल सिस्टम है उस पर मालिकाना हक हरियाणा का है। फरीदाबाद, मेवात में आगरा कैनाल के साथ जितने भी रजबाहे बने हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रजबाहे बने हैं 11 के 11 बिल्कुल कच्चे हैं। लेकिन उसमें पानी के बहाव की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर दो प्रकार की दिक्कत है। एक तो आबियाने के बदले पानी मिलने का कारण और दूसरा आबियाने की राशि जमा होने के बाद ही वे पानी छोड़ते हैं। जब पानी फालतू होता है तो छोड़ा जाता है, जब पानी की कमी होती है तब पानी नहीं छोड़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक जो पानी के राईट वाली बात है वह पिछले समय में हुई थी । मंत्री लैवल पर वार्ता करके उस मामले को निपटाया जा सकता है। चाहे लोगों से सहयोग करके या आपस में बैठकर इस पानी की समस्या को निपटाया जा सकता है ताकि निश्चित रूप से हमें जितने पानी की मात्रा मिलनी चाहिए वह मिले सके। अध्यक्ष महोदय, बंटवारे में अभी हमें यमुना का पानी दो जगह से मिलता है एक तो ताजेवाला हैड से और दूसरा औखला बैराज से मिलता है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

यमुना पर बैराज बनना चाहिए, यह एक अन्तर्राज्यीय मसला है इसको आपस में बैठकर निपटाया जा सकता है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से बैराज नहीं बना सकते। अध्यक्ष महोदय, हाउस में पानी को लेकर एक बड़े मसले पर डिस्कशन भी हुई है कि पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्या वह पानी मनुष्य और पशु के पीने के लायक भी है या नहीं । दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सारा का सारा गंद यमुना में छोड़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर गहनता से विचार-विमर्श करके एक योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि उसमें जो-जो इलाके आते हैं उनको साफ पीने के पानी की सप्लाई मिल सके। इसके लिए जो भी वाजिब कदम होगें वह हम उठायेगें।

पंडित मूलचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद और पलवल जिलों में जमीन का लगभग 80 प्रतिशत खारा पानी है। अध्यक्ष महोदय, रैनीवैल योजना के तहत यमुना के साथ 350 ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनका पहले जहाँ पानी 20 फुट पर था अब वह पानी 100,125 और 150 फुट नीचे तक चला गया है। जो पहाड़ का इलाका था जहाँ भी मीठा पानी था वह तमाम पानी अब खारा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले में तो सारा का सारा पानी खारा है। अध्यक्ष महोदय, पलवल जिले में 50 से 60 प्रतिशत खारा पानी है और फरीदबाद जिले में तो 80 प्रतिशत तक खारा पानी है। अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले 20 साल में यह पानी खारा हुआ है। जब से यमुना से रेता उठाया गया उसके कारण यमुना 20-20 फुट नीचे तक गहरी होती चली गई और उसी बहाव से पानी नीचे चला गया और पानी के जो स्त्रोत थे वे नीचे चलते चले गए। अध्यक्ष महोदय, बारिश का पानी जो यमुना से होता हुआ समुंद्र में जाकर गिरता है अगर यमुना नदी पर बैराज बना दिया जाए तो दिल्ली को मीठा पानी मिलने लगेगा तथा इससे वहां के किसानों को भी लाभ मिलेगा। गेटवे ऑफ फरीदाबाद बसने जा रहा है उसको पीने का पानी कहां से मिलेगा क्योंकि फरीदाबाद का पानी पहले ही खारा है। एक बार गड़करी जी ने ब्यान दिया था कि दिल्ली से आगरा तक यमुना के माध्यम से व्यापार चालू होगा, इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी कि यमुना पर 3 बैराज बनेंगें और तीनों बैराज से उस इलाके का पानी रिचार्ज होगा। इससे दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और गुडगाँव के किसानों को लाभ मिलेगा। आज हमारे इलाके में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, हमें आगरा कैनाल का बंटवारे के माध्यम से जो पानी पीने के लिए मिलता है वह हमें यमुना का पानी नहीं मिलता है बल्कि वह दिल्ली के बड़े-बड़े उद्योगों व कम्पनियों के गड्ढों का गन्दा पानी मिलता है। अगर साफ पानी मिलता तो हम उस पानी को पीकर गुजारा कर सकते थे लेकिन वह पानी तो खेती के लायक भी नहीं है। अगर यह बैराज बन जायेगा तो दक्षिणी हरियाणा की यह समस्या खत्म हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य की बिल्कुल जायज है। इन्होंने इसे गंभीरता के साथ इंगित किया है और एक जो विकास में असंतुलन रहा है हमारे सामने आज इसके दुष्फल आ रहें हैं। अध्यक्ष महोदय, अति खनन के कारण फरीदबाद की बड़खल लेक भी समाप्त हो गई है और कल सदन में एक माननीय सदस्य ने पॉजिटिव पॉयंट उठाया था कि अगर हम यमुना से रेता नहीं उठायेंगे तो पानी हमारी तरफ आ जायेगा तो यमुना हमारी तरफ बढ़ जायेगी। यमुना को गहरा करना जरूरी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यमुना को गहरा करने से ही यह समस्या आई है इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है। इस इलाके में पानी की

समस्या को लेकर, यमुना के प्रदूषण को लेकर निश्चित रूप से सरकार कंसर्ड है और सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है कि किस प्रकार से हमें बरसात के दिनों में तालाब के रुप में जो भी सरप्लस पानी मिलता है, उस समय हरियाणा के अधिकांश जोहड़ पानी से भर जाते है मेवात में भी हम एक तालाब विकसित कर रहे हैं। बाकी स्थानों पर हम ऐसी जगह खोज रहे हैं जहां पर अंडर ग्राउण्ड वॉटर कम होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी इस सदन को बताया है कि एक करोड़ एकड़ फीट पानी जमीन से निकाल रहे है और रिचार्ज केवल 60 लाख एकड़ फीट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 40 लाख एकड़ फीट का गैप है, इससे बहुत सारे इलाके डार्क जोन बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पानी की क्वालिटी का सवाल है, इस बारे में विभाग इस प्रकार की योजना बना रहा है कि सरप्लस पानी को और वर्षा के पानी को रोककर तथा बरसात के दिनों में नहरों में भी जो हमारी सर्वाधिक सप्लाई करने की जो स्थिति होती है, उसको ध्यान में रख कर ग्रामीण जोहड़ों के माध्यम से और जहां भी जमीन हमको उपलब्ध होती है, वहां पर बड़े-बड़े तालाब बना कर उस पानी को रोका जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की तरफ सरकार बढ़ रही है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में बताया कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से सारा साल पलवल जिले और फरीदाबाद के किसानों को पानी दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों कैनालों से मेवात का भी संबंध है और अभी तक वर्षों से ऐसे बहुत से रजबाहें हैं जिनके नाम मैं नोट करवाना चाहता हूँ। थमेली वन रजवाहा, महझोली रजवाहा, बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री, उटावड़ माईनर, नीमका माईनर, बिछोड़ माईनर, पुन्हाना माईनर, बंचारी माईनर और डकौरा माईनर है। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे माईनर हैं जिनमें पिछले लगभग 10-15 वर्षों से पानी की एक बूंद भी नहीं गई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वायदा किया हुआ है कि टेल तक पानी पहुँचायेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसान भाई भी बड़ी आशा के साथ नजर लगाकर बैठे हुए हैं कि कब पानी आयेगा? मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि ये किसान कब तक आपकी सरकार का इंतजार करेंगे? माननीय मंत्री जी कब तक रजबाहों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचेगा इसकी समय अवधि बताने का कष्ट करें।

श्री ओमप्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, जो कैनाल सिस्टम है जिस पर मालिकाना हक है और हम उस पर काम कर सकते हैं उसकी समय सीमा मीडिया के माध्यम से भी हमने कही है। अधिकांश नहरों में हमने रजबाहों में टेल तक पानी पहुँचाया है। जिस पर कोई ना कोई दिक्कत जैसे लैवलिंग की है या लिफ्ट इरीगेशन आदि की जरुरत होती है, सरकार ऐसी दिक्कतों को दूर करते हुए आगामी 6 महीनों में पानी पहुँचाने का काम करेगी लेकिन उत्तरप्रदेश मालिकाना हक का कैनाल सिस्टम है, इसकी दूसरी बड़ी दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रुप से पहल करके एक बार भी उत्तरप्रदेश में मंत्री स्तर पर इस विषय में वार्तालाप करते हुए इस कैनाल सिस्टम को फिर से उस इलाके के किसानों के लिये सुचारू रूप से शुरु करवाने के लिये हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री केहर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों ने हरियाणा के किसानों के आबियाने माफ किये हैं। हम भी हरियाणा में रहते हैं। उत्तरप्रदेश की आगरा कैनाल जरूर है, मगर 14 करोड़ रुपये की राशि आबियाने के तौर पर आगरा कैनाल की बकाया है यह ज्यादा राशि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे गम्भीरता से ले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो

[श्री केहर सिंह]
14 करोड़ रुपये की राशि आबियाने की बकाया हैं उस राशि को सरकार वहन करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि उसके बाद पानी रैगुलरं चलता रहा तो किसान एक साल के अन्दर इस राशि को लौटाने में सक्षम हो जायेगें। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि 14 करोड़ रुपये की आबियाने की राशि का प्रावधान करके उत्तरप्रदेश की सरकार को यह राशि दी जाये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक निवेदन किया है, सरकार इस पर विचार करेगी।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मेरा असंध विधान सभा क्षेत्र में जीन्द रोड़ और कैथल रोड़ दोनों के बीच की जो घरों की जमीन है वह बहुत खराब है क्योंकि वहां पर खारा पानी है वह न तो पीने के लायक है और न ही खेती के लायक है। अध्यक्ष महोदय, नहरों की बात चल रही थी तो मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ निर्दक ड्रिस्ट्रीब्यट्री जा रही है, यदि उस पर 1 लाख 70 हजार आर. डी. पर अगर एक छोटा सा माईनर बनाया जाये तो उसके कारण गंगा तेड़ी, मुण्ड और असंध का जो एरिया है उसमें पानी जायेगा और इससे वहां के किसानों को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रपोजल वर्ष 1986 में तैयार हुआ था। वर्ष 1986 में तैयार होने के बाद वह पैंडिंग पड़ी है। इस पर कोई गौर नहीं किया गया। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार के समय में यह पूरा हो जाएगा जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में जरुर संज्ञान करें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अलग है लेकिन ऐसी प्रपोजल्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं और जो थायबिलिटी है हम उस पर विचार करेंगे।

श्री उदयभान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों से जो आबियाना लिया जाता है उसी तर्ज पर समान आबियाना दर के हिसाब से एक जैसा आबियाना लेने के लिए पलवल और मेवात जिले के किसानों के लिए भी क्या सरकार कोई योजना बनाएगी? जैसा माननीय सदस्य श्री केहर सिंह रावत ने कहा कि 14 करोड़ का अमाउंट कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। उस अमांउट को भरकर जो शुरू के प्वाइंट हैं जैसे हथीन रजबाहा है जो किठवारी हैड से निकलता है, होडल रजबाहा और हसनपुर रजबाहा है उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते है हरियाणा के स्टार्टिंग प्वाइंट पर बहुत ज्यादा गाद भरी रहती है क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इस कैनाल की सफाई नहीं कराई जाती है। गाद भरी होने से हैड में पानी की क्षमता भी कम हो जाती है इसलिए आप इस कैनाल की सफाई करवाने का प्रबंध करें। मेरा अगला सवाल पानी की क्वालिटी से संबंधित है। सरकार हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट और वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली को यमुना का शुद्ध पानी देती है लेकिन हमारे इलाके को गटर का गंदा प्रदूषित, कैमिकल युक्त पानी पीना पड़ता है। इससे हजारों लोगों को हड्डी के रोग और कैंसर तथा अन्य बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली के 26 नालें यमुना में लगातार पड़ रहे हैं। अत: जब आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बात करें तो आप सुनिश्चित करें कि जो यमुना एक्शन प्लान के तहत निश्चित हुआ था कि दिल्ली के जो भी नाले यमुना में डाले जाएं वे ट्रीट होकर पड़ने चाहिएं ताकि हमारे लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया हो सके। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2014 में ही हमने उत्तर-प्रदेश की सरकार के सिंचाई विभाग को यमुना की सफाई के लिए 12 लाख, 95 हजार रूपये दे दिये हैं। सरकार की सोच काफी व्यापक है। हालांकि हम अभी सभी किसानों को समान भाव पर पानी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हमने बिजली की दरें हरियाणा प्रदेश में इतनी कम की है कि आबियाना और बिजली के बिल में ज्यादा गैप नहीं रहा है। यदि कोई किसान डीजल के इंजन से खेत में पानी देता है तो उसे वह सिंचाई काफी महंगी पड़ती है। एक सिंचाई पर एक हजार रूपये खर्च होते हैं और 5 बार सिंचाई करने पर 5 हजार रूपये खर्च करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हर किसान को एक भाव पर पानी प्राप्त हो। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम इन गैप्स को दूर करने के लिए योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं।

***तारांकित प्रश्न संख्या 29**

Construction of Water Courses

***29 Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :

a) the status of construction of water courses of 9" width in village Mahra, Tehsil Sonepat and Mahipar; and

b) whether these water courses are likely to be constructed in current financial year ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

क) गांव माहरा में सरदाना रजवाहे की बुर्जी नं0 27114-दाएं के मोगे पर तथा गांव महीपर में सिसाना रजवाहे की बुर्जी नं0 17440-दाएं के मोगे पर जलमार्गों का पुनरोद्धार 9 इंच चौड़ी दीवार के साथ किया जाना है। कार्य अभी आरंभ करना है।

ख) इन जलमार्गों को अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में आरम्भ किए जाने की प्रस्तावना है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सिंचाई प्रायरिटी पर है। माननीय सदस्य का प्रश्न एक चौड़े नाले के विषय में है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री का किसानों की परवाह करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गांव गांवड़ी, चटिया देवा और भादी में जहां का इलाका बरानी है वहां भी खालों के लिए वाटर रिजरवायर्स सोयायटी के प्रस्ताव सरकार के पास है। क्या सरकार उनको भी बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अलग है। हमरा विचार है कि हमारा संकल्प हर खेत को 5 वर्ष में पानी देना है। हम अंडरग्राउंड वाटर पाईपलाइन्स और माइक्रो

इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं। यूजर ऐसोसिएशन के सहयोग से पानी की चोरी भी रूके और हमारे पास जो एक करोड़ एकड़ फीट पानी है उसको हम अधिक से अधिक खेतों तक पहुंचा सकें इसके लिए निश्चित रूप से हमने एक विजिन डाक्यूमैंट्री तैयार किया है और उसी हिसाब से साल दर साल हम उस पर आगे बढ़ेंगे।

श्री रामचन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के रानिया विधान सभा क्षेत्र में एक सुल्तानपुरिया गाँव पड़ता है जिसका जमीनी पानी पीने के लायक नहीं है और घग्गर नदी का पानी भी उस गाँव को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी जोधड़ गाँव जोकि सुल्तानपुरिया गाँव से दो किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है वहां से एक रजबाहा बनाकर इस गाँव को पीने का पानी देने की कोई व्यवस्था करेंगे। इस गाँव की तरफ से सरकार के संज्ञान में कई बार यह मामला लाया गया है और इसी कारण पिछले लोकसभा चुनाव का इस गाँव ने बहिष्कार किया था। क्या सुल्तानपुरिया गाँव को घग्गर नदी का पानी मिल पायेगा ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल अलग से है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि इस किस्म की समस्याएं जहां पर भी हैं उन सभी गाँवों में पानी पहुंचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस गाँव में भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करेंगे।

श्री बलकौर सिंह कालांवाली : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय मेरा हल्का कालांवाली रोड़ी हल्के में पड़ता था। मेरे हल्के कालांवाली में उस समय बहुत ज्यादा सेम थी। उस समय उस सेम को निकालने के लिए चौटाला साहब की सरकार ने एक ड्रेन को खुदवाया था जो ड्रेन रोड़ी, सुरतिया, रोहण, फग्गु, देसू खुर्द, बड़ा गुढ़ा, भादड़ा, सूबा खेड़ा, बीरूवाला, गूढ़ा ढाबा और भग्गु गाँव से होती हुई घग्घर नदी में पड़ती थी। उस समय यह सेम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब वह ड्रेन वैसी की वैसी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उस ड्रेन को घग्गर नदी से वापिस लाना चाहिए क्योंकि उस ड्रेन में थोड़ी सी ही खुदाई और सफाई की जरूरत है। जब पानी आता है तो थोड़े से खेतों में उस ड्रेन का पानी पहुंचता है। ज्यादा खेतों में पानी पहुंचाने के लिए उस ड्रेन की खुदाई करवाई जाये। इस काम के लिए न तो कोई रकबा एक्वायर किया जाना है और न ही सरकार का इस काम पर ज्यादा खर्च आयेगा। थोड़े से खर्चे से ही बहुत ज्यादा किसानों को इससे फायदा हो सकता है। यह बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री ओमप्रकाश धनखड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ड्रेन की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। हम निश्चित रूप से उस ड्रेन को उपयोगी बनायेंगे ताकि वह ड्रेन पानी की निकासी का माध्यम बन सके। माननीय सदस्य के सुझाव की तरफ विभाग जरूर गौर करेगा और उस ड्रेन को हम जरूर व्यवहारिक बनायेंगे।

Construction work of Jind Bye-Pass

***44. Shri Hari Chand Middha :-** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) the time by which the construction work of Bye-pass of Jind city is likely to be completed which is under construction since the year 2008;

(b) the percentage of construction work of the abovesaid Bye-pass has been completed so far;

(c) the amount to be spent on the abovesaid Bye-pass;

(d) whether any time limit has been fixed to complete the construction of the abovesaid Bye-pass; and

(e) the total amount spent on the construction work of the abovesaid Bye-pass so far togetherwith the names of the companies to whom the Contract of construction work has been given ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) जीन्द शहर के बाईपास, रोहतक रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 71) से गोहाना रोड, सफीदों रोड नरवाना तक असन्ध रोड को पार करती हुई (राष्ट्रीय राजमार्ग 71) जिसकी लम्बाई 15.65 कि0मी0 है, के शेष कार्य का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के कि0मी0 239.000 (पंजाब सीमा) से कि0मी0 307.000 (जींन्द) को चारमार्गीय करने की परियोजना के अधीन डिजाईन, बनाओ, वित्त, चलाओ और हस्तांतरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.) के आधार पर किया जाना है। इस शेष कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) अभी तक राज्य सरकार द्वारा हांसी रोड से भिवानी रोड तक 6.30 कि0मी0 की लम्बाई का दो मार्गी बाईपास का कार्य पूरा किया जा चुका है। यह बाईपास हांसी रोड से शुरू होकर भिवानी रोड, मौजूदा उत्तरी बाईपास (रोहतक रोड से गुजरता हुआ) से गोहाना रोड तक तथा गोहाना रोड से असन्ध रोड तक (सफीदों रोड से गुजरता हुआ) जोकि राज्य सरकार द्वारा शुरू में बनाना प्रस्तावित था, की कुल लम्बाई 15.74 कि0मी0 का 40 प्रतिशत है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा शुरू में प्रस्तावित बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत 14.41 करोड़ रुपये थी। इसके लिए अनुमानित निर्माण लागत 17.71 करोड़ रुपये थी।

रोहतक रोड़ से नरवाना रोड तक 15.65 कि0मी0 लम्बाई का चारमार्गी बाईपास जोकि अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पंजाब सीमा से जींद तक की चारमार्गीय परियोजना के अधीन बनाना प्रस्तावित है की अनुमानित लागत 202.379 करोड़ रुपये है।

[श्री नरबीर सिंह]

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रियायती ने पंजाब सीमा से जींद की चारमार्गीय परियोजना के शीघ्र समाप्ति के लिए आवेदन किया है इसलिए रोहतक रोड तक के बाईपास की समय सीमा अभी निर्धारित की जा सकती।

(ङ) राज्य सरकार ने हांसी रोड से असन्ध रोड तक के बाईपास के निर्माण पर 16.83 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। निर्माण कार्य मैसर्ज सिंगला इंजीनियर एण्ड कॉन्ट्रैक्टर, मैसर्ज झण्डू कंस्ट्रक्शन कम्पनी (पुल कार्य) व मैसर्ज सहदेव कुमार कोन्ट्रैक्टर हिसार द्वारा किया गया था।

श्री हरि चन्द मिढा: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने प्रश्न में बहुत कुछ जानकारी मांगी थी लेकिन मेरे प्रश्न का अधूरा उत्तर ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में दिया गया है। मैं यहां पर किस लिए आया था और मैं अपने हल्के की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा ? मुझे तो सरकार से बहुत उम्मीद थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब वे कुछ तो बदलाव लायें।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री मिढा जी को बताना चाहूंगा कि इस नैशनल हाईवे के निर्माण के लिए टैंडर हुए थे। कई ठेकेदार तो कीमतें बढ़ने की वजह से काम छोड़कर चले गये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि किसी ठेकेदार को पर्यावरण विभाग, किसी ठेकेदार को वन विभाग तथा किसी ठेकेदार को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से समय पर क्लीयरैंस नहीं मिलती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे तथा हमारी सरकार प्रयत्नशील है कि इस सड़क का निर्माण बहुत जल्द ही किया जाये क्योंकि वास्तव में ही वहां पर बड़ी भारी दिक्कत है। माननीय विधायक साथी के अलावा जींद के और लोग भी इस बारे में शिकायत करते हैं कि जींद का यह बाई-पास बनना चाहिए क्योंकि वहां पर बाई-पास बनाने का कार्य बहुत दिनों से अधूरा है। माननीय सदस्य श्री ढुल साहब ने भी सदन में इस बारे में 2-3 बार जिक्र किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इस सड़क व बाई-पास का निर्माण कार्य पूर्ण करवायेंगे।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र भगवान् श्रीकृष्ण की भूमि है तथा देश-विदेशों से वहां पर टूरिस्ट आते हैं तथा कुरूक्षेत्र शहर को क्रॉस करके जब वे तीर्थ-स्थल पेहोवा जाते हैं तो वहां पर बाई-पास न होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा रहता है तथा देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट उस जाम में फंस जाते हैं इसलिए मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ट्रैफिक की इस समस्या के निदान हेतु कुरूक्षेत्र में एक बाई-पास का निर्माण करवाया जाये ताकि देश-विदेश से आने वाले टूरिस्टों को भी अच्छा लगे।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह अलग से प्रश्न किया है। माननीय विधायक साथी मुझे रोज मिलते रहते हैं। कृपया वे मुझे मेरे कार्यालय में आकर मिल लें, मैं उनके इस प्रश्न का इनको संतोषजनक जवाब दे दूंगा।

श्री अनूप धानक: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के खेदड़ गाँव से भैणी बादशाहपुर रोड पर मोटा रोड़ा बिछाया जा चुका है, लेकिन उसका कार्य बंद पड़ा है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी उस कार्य को पूरा करवाने का कष्ट करें तथा यह भी बतायें कि यह कार्य बंद क्यों पड़ा है ? इसके अतिरिक्त मेरे उकलाना विधान सभा क्षेत्र में उकलाना से कुंदनपुरा, गाँव खेदड़ से दौलतपुर, गाँव बधावड़ से ढाड, कनोह से किरमारा, साहू से चमारखेड़ा, साहू से खैरी, पाबड़ा से साहू, बुढ़ा खेड़ा बाई पास से जी.टी. रोड, दौलतपुर से फरीदपुर, बिठमड़ा से गैबीपुर तथा सनियाना से चमारखेड़ा तक की सभी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाने का कार्य करवायें।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से इनकी सड़कों के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन मैंने पूरे सदन में पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो गड्ढे छोड़े हैं, हमारी सरकार 5 साल में उन सब गड्ढों को भरने का काम अवश्य करेगी तथा जितना भी संभव हो सकेगा, हम प्रदेश के अंदर सभी सड़कों की रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद माना है कि बाई-पास को लेकर जींद जिला में बड़ी भारी समस्या है। वर्ष 1972 में जब चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तथा मेरे आदरणीय पिता चौधरी दल सिंह विधायक थे, यह बाई-पास उस समय मंजूर हुआ था। उसके बाद 14 मई, 2005 को बड़े-बड़े बैनर लगाकर यह बाई-पास 11-00 बजे मंजूर किया गया और इसका पैसा भी रिलीज कर दिया गया। वर्ष 2006 से 2011 तक की कैग रिपोर्ट 2012 में आई। जो 38.70 करोड़ रूपये दिए गए थे वे 6 साल के बाद वापिस ले लिए गए। इस प्रकार की दुर्दशा जींद की थी। अध्यक्ष महोदय, आज गन्ना किसानों की बहुत बुरी हालत है और रोजाना इस सड़क पर एक्सीडैंट्स होते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक यह बाई पास नहीं बनता तब तक क्या सरकार कोई अल्टरनेटिव रोड बनाकर उनको सहायता देगी।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन्होंने 1972 का जिक्र किया है लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि 1972 के बाद तो बहुत सी सरकारें आईं और बहुत सी सरकारें गई। हमारी सरकार को तो बने 130-132 दिन ही हुए हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इनकी तसल्ली हो सकती है और जो कुछ सरकार प्रावधान कर सकती है वह करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Flowing of Dirty Water

*59. **Shri Lalit Nagar :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that dirty water of sewerage system from Delhi flowing in the colonies of Tigaon Assembly Constituency; and

[Shri Lalit Nagar]

(b) if so, the steps taken by the Government to check the flow of dirty water of sewerage as referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)

(क) नहीं, श्रीमान् जी। चर्चाधीन क्षेत्र में सीवर प्रणाली द्वारा गंदे पानी का बहाव नहीं है। तथापि दिल्ली की कुछ कॉलोनियों में बरसाती पानी के माध्यम से गन्दा पानी तिगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र में प्रवेश करता है।

(ख) कथित गन्दे पानी के प्रभावी निष्पादन के लिए निवारक उपाय करने हेतु दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से सहमति प्राप्त करने के प्रयास किये जाएंगे।

To Open a Horticulture University in Village Bahin

***329. Shri Kehar Singh :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Horticulture University in village Bahin of Hathin Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :- श्रीमान् जी नहीं, सरकार बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में उपयुक्त जगह का आंकलन कर रही है।

Thermal Power Plants in Haryana

***533 Smt. Santosh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Thermal Power Plants were established by Government between 2004 to 2014; if so, the number of such plants together with the cost of each plant; and

(b) the capacity of each plant together with the quantum of Power produced during abovesaid period together with the present status of energy production of the aforesaid each plant ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) तथा (ख) का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) वर्ष 2004 से 2014 के दौरान सरकार द्वारा स्थापित पावर थर्मल प्लांट तथा उन सब की लागत का विवरण निम्न है :

क्रम संख्या	स्थापित यूनिट	कमीशनिंग की तिथि/ कमर्शियल ऑपरेशन तिथि (सीओडी)	क्षमता	स्वयं द्वारा	यूनिट की लागत (रुपये करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6
1.	यूनिट-7 पी.टी.पी.एस., पानीपत	28.09.2004	250 मैगावॉट		1871.20
2.	यूनिट-8 पी.टी.पी.एस, पानीपत	28.01.2005	250 मैगावॉट		
3.	यूनिट-1, डी सी आर टी पी पी, यमुनानगर	14.04.2008	300 मैगावॉट	एच पी जी सी एल	2186.86
4.	यूनिट-2, डी सी आर टी पी पी, यमुनानगर	24.06.2008	300 मैगावॉट		
5.	यूनिट-1, आर जी टी पी पी, हिसार	24.08.2010	600 मैगावॉट		4112.00
6.	यूनिट-2, आर जी टी पी पी, हिसार	01.03.2011	600 मैगावॉट		
7.	यूनिट-1 आई जी एस टी पी पी, झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%)	05.03.2011	500 मैगावॉट	हरियाणा सरकार का एनटीपीसी तथा दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम	10131.82 (हरियाणा द्वारा इक्विटी) (644.10 करोड़ रुपये)
8.	यूनिट-2 आई जी एस टी पी पी झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%)	21.04.2012	500 मैगावॉट		
9.	यूनिट-3 आई जी एस टी पी पी, झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%)	26.04.2013	500 मैगावॉट		

(बी) वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2014-15 (फरवरी 2015 तक) स्थापित किये गये थर्मल पावर प्लाटों की क्षमता के साथ उनकी बिजली उत्पादन की मात्रा तथा उनकी बिजली उत्पादन की वर्तमान स्थिति :

क्रम संख्या	स्थापित यूनिट	क्षमता	2004-05 से लेकर 2014-15 (फरवरी 2015 तक) बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	बिजली उत्पादन की वर्तमान स्थिति
1.	यूनिट-7 पी.टी.पी.एस., पानीपत	250 मैगावॉट	18660.57	प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन करने के लिए उपलब्ध है। हालांकि प्लांट बिजली वितरण निगमों की आवश्यकता के अनुसार ही बिजली उत्पादन कर रहे है।
2.	यूनिट-8 पी.टी.पी.एस. पानीपत	250 मैगावॉट	19106.86	
3.	यूनिट-1, डी सी आर टी पी पी, यमुनानगर	300 मैगावॉट	13031.03	
4.	यूनिट-2, डी सी आर टी पी पी, यमुनानगर	300 मैगावॉट	9281.44	
5.	यूनिट-1, आर जी टी पी पी, हिसार	600 मैगावॉट	12785.73	
6.	यूनिट-2, आर जी टी पी पी, हिसार	600 मैगावॉट	10267.25	
7.	यूनिट-1, आई जी एस टी पी पी, झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%)	500 मैगावॉट	18365.14 एम यू (दिसम्बर 2014 तक की कुल उत्पादित बिजली में से 6150.86 एम यू हरियाणा की सप्लाई किए गए है।	
8.	यूनिट-2 आई जी एस टी पी पी, झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%	500 मैगावॉट		
9.	यूनिट-3 आई जी एस टी पी पी, झज्जर (हरियाणा का हिस्सा 50%)	500 मैगावॉट		

To Replace the Obsolete Electric Wires

*72 **Smt. Kiran Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electric wires in Bhiwani District; if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् आवश्यकता अनुसार समय-समय पर पुरानी बिजली तारों को बदला जाता है। जिला भिवानी में भी आवश्यकता अनुसार बदला जाएगा।

Facilities in the Government Hospital Julana

*96 **Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the newly built Government Hospital at Julana is likely to be made fully operational togetherwith the facilities which were originally conceptualized to be made available in the hospital alongwith the total number of posts of all categories including doctors lying vacant in the hospital ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

श्रीमान् जी, जुलाना में पहले से ही वर्ष 1989 से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है और यह दिनांक 30.08.2013 से इसके नए भवन में कार्य कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुलाना में सभी श्रेणियां जिसमें डाक्टर भी शामिल है के 65 पद स्वीकृत है, जिसमें से 55 पद भरे हुए है तथा 10 पद रिक्त है।

To Solve The Problem of Stray Animals

*107 **Shri Balwan Singh :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the problem of stray animals in tehsil Fatehabad togetherwith the time by which problem is likely to be solved ?

कृषि मन्त्री, (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

वक्तव्य

श्रीमान जी, जिला प्रशासन द्वारा तहसील फतेहाबाद में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु अग्रसक्रिय कदम उठाये गये हैं। वर्तमान नगरपरिषद फतेहाबाद द्वारा स्थानीय नागरिकों की सहायता से दो गउशालायें चलाई जा रही है जिनमें 495 बैल/सांड, 104 गायें तथा 48 बछड़ों का रख-रखाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजि संस्थानों द्वारा जिला फतेहाबाद में 35 गउशालायें चलाई जा रही है जिनमें भी कई बार आवारा पशुओं को रखा जाता है।

आगे, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु एक विस्तारयुक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। लेकिन मामले की जटिलता के कारण समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

Bad Condition of Sewerage Lines

***524 Smt. Seema Trikha :-** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the sewerage lines laid down about 60 years ago in town Badkhal of Faridabad are in very bad condition; if so, whether there is any policy of the Government to lay down the new sewerage lines ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : यह सत्य है कि बड़खल निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली एन0आई0टी0 फरीदाबाद में सीवर लाइनें 60 वर्ष पूर्व बिछाई गई थी और वर्तमान में वह चालू अवस्था में है। नगर निगम, फरीदाबाद का नई सीवर लाईनें बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, सीवरेज प्रणाली की कार्य-कुशलता बढाने के लिए, नगर निगम फरीदाबाद सभी ड्रेन व सीवर लाइनों को मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व साफ करवायेगा, इसके लिए यदि आवश्यक होगा तो मशीनें क्रय की जायेंगी अथवा किराये पर ली जायेंगी ताकि क्षेत्र का सीवर बंद न हो।

इसके अतिरिक्त बड़खल कस्बें/गांव में जहां लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा सीवरेज के ऐसे सभी भागों का निरीक्षण करवाया जायेगा तथा इन सभी भागों का धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अग्रता के आधार पर मुरम्मत/प्रतिस्थापन करवाया जायेगा।

Construction work of Kaushalaya Dam

***539. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that despite the initial negative report of the year 1995, the construction work of Kaushalaya Dam was started during the year 2005; if so, thereasons thereof;

(b) whether it is a fact that the initial cost of the project was Rs. 55 Crores but later it is enhanced to Rs. 217 Crores; if so the reasons thereof;

(c) whether the Government has decided to investigate in this regard; if so, the details thereof;

(d) the quantum of water being supplied to Panchkula, Kalka and Pinjore from the Kaushalaya Dam; and

(e) whether the dimenetions, such as Length, Breadth and Height of the Kaushalaya Dam was fixed to give benefit to some big colonizers?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) से (ङ) श्रीमान जी, कौशल्या बांध के निर्माण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति पर सरकार ने जांच करने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरों को आदेश दिया है जिसे राज्य सतर्कता ब्यूरों ने जांच संख्या 1 दिनांक 06.01.2015 को दर्ज कर लिया है। प्रश्न बारे असली स्थिति जांच पूर्ण होने तथा रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी।

R.O. System for Supply of Drinking Water

***115. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether the Haryana Government has formulated any scheme to provide R.O. system on the water works for supply of drinking water in all the villages of Dabwali Constituency in District Sirsa; if so, details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

To allot the Oustees Plots

***132 Shri Jai Tirath :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government has charged money from the farmers of Rai constituency for allotting the oustees plots in the Rajiv Gandhi Education City; if so, the time by which the oustees plots will be allotted to the said farmers ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्री मान जी,

विस्थापित नीति अनुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पश्चात योग्य विस्थापितों को 12 मास में प्लाट अलाट करने का प्रयास किया जा रहा है।

To Handover the Residential Secters

***234 Shri Umesh Aggarwal :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the residential sector developed by HUDA in Gurgaon to the Municipal Corporation; if so, whether the Haryana Urban Development Authority will be responsible for the development in these sectors :

b) The name of the Department who will be the owner of non-allotted residential plots and commercial plots; and

c) Whether the private colonies developed by the builders have also been handed over to Municipal Corporation ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

श्री मान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

क) हां, श्री मान जी, स्थानीय निकाय को हस्तांतरण उपरांत हुडा इन क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अनुमोदित नक्शे के अनुसार अगर कोई कमी होगी, वह हुडा द्वारा दूर की जायेगी।

ख) हुडा द्वारा विकसित किए गए क्षेत्रों को स्थानीय निकाय को हस्तांतरण उपरांत भी हुडा उन क्षेत्रों में अन-आंबटित सम्पत्तियों का मालिक होगा।

[श्री मनोहर लाल]

ग) नहीं, श्री भान जी, यद्यपि निजी लाईसेंस धारकों द्वारा विकसित की गई कालोनियां उनके रिहायशी प्रमाण पत्र हासिल करने के पांच वर्ष उपरांत स्थानीय निकाय को हस्तांतरित की जायेगी।

To Provide facilities at Babail Purchase centre

***120. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the facility of Boundary wall, shed, electricity, Drinking Water together-with the repair of damaged platform of Babail purchase centre ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

जी, हां, श्रीमान्।

यद्यपि, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार खरीद केन्द्र में स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि या तो बोर्ड को स्थानांतरित की जानी चाहिए अथवा बोर्ड के नाम 33 साल या उससे अधिक की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दी जानी चाहिए। यदि ग्राम पंचायत, बबैल बोर्ड को उक्त भूमि स्थानांतरित करती है तो वहां अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं का विकास कर दिया जायेगा।

Draining out of Rainy Water

***154. Shri Pirthi Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is fact that the rain water accumulates in the Narwana Bus Stand during the rainy season; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve this problem togetherwith the time by which the said problem is likely to be solved ?

परिवहन मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान्। आगामी वित्त वर्ष में एक स्थाई पानी निपटान पम्प हाउस लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Tubewell installed for Drinking Water

***136 Shri Naseem Ahmed :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the number of tubewells installed for drinking water in Firozpur Jhirka during the year 2013 and 2014 togetherwith the village-wise details of the Tubewells likely to be installed in the year 2015 ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, वर्ष 2013 में फिरोजपुर झिरका में एक नलकूप ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया था। एक नलकूप फिरोजपुर झिरका शहर में लगाया गया था वर्ष 2014 में एक नलकूप ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया था और फिरोजपुर झिरका शहर में कोई भी नलकूप नहीं लगाया गया था। वर्ष 2015 में 19 नलकूप लगाने के लिए अनुमान की मंजूरी दे दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

1	अगोन	3 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 25.20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
2	बेडड	2 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 16.80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
3	बाडोपुर	यह आगोन गांव क्रमांक संख्या नं0 1 में सम्मिलित है।
4	ढोडल	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
5	डोगरी	यह हमजापुर में क्रमांक संख्या नं0 7 में सम्मिलित है।
6	घाटा शमशाबाद	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
7	हमजापुर	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
8	गुजर नंगला	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 7.80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
9	हिरावरी बामाथेरी	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
10	खेरला खुर्द	यह हमजापुर में क्रमांक संख्या नं0 7 में सम्मिलित है।
11	कोलगोन	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
12	पाडला शाहपुरी	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 9.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
13	रानयाला फिरोजपुर	1 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 8.40 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।
14	रावली	2 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेट में 16.75 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
15	साकरास	4 नं0 नलकूप की स्थापना के लिए एस्टीमेंट में 33.60 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है और नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त नलकूपों की जरूरत का अध्ययन किया जा रहा है।

सदस्यों को लैपटॉपस इत्यादि देने बारे में सूचना देना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा लैपटॉप खरीदने के आर्डर दे दिए गए हैं और जल्दी ही आपको लैपटॉप और प्रिंटर उपलब्ध करवा दिए जाएंगें। जैसाकि आप सबको विदित है कि आजकल सरकार की ओर से सभी प्रकार की इन्फर्मेशन की सोफट कापी सी.डीज. के माध्यम से प्रदान की जा रही है इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सबकी सुविधा के लिए 10 कम्प्यूटर्ज और प्रिंटर हरियाणा विधान सभा की समिति कक्ष में इन्सटाल करवा दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए विधान सभा के कर्मचारी प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगें। आप जिस इन्फर्मेशन की कापी लेना चाहते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि आपने कम्प्यूटर मुहैया करवा दिए लेकिन मै कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा को वाई फाई भी करवा दो ताकि लागों को इसका फायदा हो सके।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आपने विधायकों को लैपटॉप उपलब्ध करवा दिए जो बहुत अच्छी बात है माननीय सदस्य जयप्रकाश जी ने विधानसभा में आवाज उठाई थी और जिस पर चर्चा चली थी कि बहुत से विधायकों को कम्प्यूटर में एक्सपर्ट होने में टाइम लगेगा तो क्या कम्प्यूटर आप्रेटर्स की भी सहायता विधायकों को दी जाएगी ताकि वे सारा काम ई-मेल द्वारा और पेपरलैस होकर कर सकें जोकि सरकार का सपना भी है।

श्री अध्यक्ष : इस पर हम विचार कर रहे हैं

वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

1. इस गरिमामय सदन में अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य और सम्मान की बात है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे इस गरिमामय सदन के सदस्य के रूप में तथा कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री के रूप में हरियाणावासियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

2. हमारी सरकार एक निर्णायक एवं सकारात्मक जनादेश के साथ सत्ता में आई है। यह जनादेश है तीव्र वृद्धि, संतुलित क्षेत्रीय विकास और सुशासन के लिए। यह जनादेश भ्रष्टाचार, विभाजक तथा भेदभावपूर्ण राजनीति के विरुद्ध भी है। हमारी सरकार एक ऐसे राजनैतिक दर्शन से प्रेरित है जो लोकतंत्र की सच्ची भावना का पक्षधर है। हमारा मानना है कि हरियाणा के लोग ही इस सरकार के असली मालिक हैं। हमारी सरकार शासन के 'सबका साथ–सबका

विकास' के हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में निहित संवाद एवं जवाबदेही पर आधारित सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कार्य करेगी। हमारी सरकार जाति, नस्ल, क्षेत्र या पंथ, सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों को एक संघटित इकाई मानकर विकास एवं समृद्धि के समान अवसर उपलब्ध करवाने में विश्वास रखती है। सशक्त स्थानीय स्वशासन में हमारा अखण्ड विश्वास है और हम स्थानीय शासन की संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निरन्तर प्रयास करेंगे।

3. हमारी सरकार बजट को मात्र किसी एक वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखा–जोखा के रूप में नहीं देखती। यह आर्थिक रणनीति के बारे में हमारे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है और सामाजिक विकास, परिवर्तन एवं समावेश का एक माध्यम भी है। इसलिए, मैं इस अवसर पर राज्य के आर्थिक विकास पर हमारी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करूंगा और इसे यथार्थ में बदलने के लिए आगामी 5 वर्षों की हमारी रणनीति को व्यक्त करूंगा। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों एवं स्तरों तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समावेश करके, संतुलित विकास–नीति के माध्यम से हरियाणा को सही विकास संभावना तक ले जाने का प्रयास करेगी। हम हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए विकास के भरपूर अवसर बनाने के लिए अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति तथा जनसांख्यिकीय बढ़त का पूरा लाभ उठाएंगे। हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखती है और हम गरीब तथा वंचित लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अथक प्रयास करेंगे। हमारे युवाओं के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर पैदा करने पर हमारा सम्पूर्ण ध्यान रहेगा। हम विकास नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने के तरीकों में एक व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अब तक की राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित शासन–शैली के विपरीत, हमारी सरकार मजबूत आर्थिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक नीति विकल्पों द्वारा निर्देशित होगी। संसाधनों के मनमाने एवं पक्षपातपूर्ण, तर्कहीन आबंटन एवं दूषित पूंजीवाद के विपरीत, हम संसाधनों के उपयुक्त आबंटन, संतुलित विकास और आर्थिक लाभ के वितरक न्याय की रणनीति अपनाएंगे। अदूरदर्शी तथा मनमाने नियोजन के स्थान पर सतत् विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण, समन्वित नियोजन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाएगा। हम सरकारी प्रदायगी तंत्र की साधुता एवं दक्षता पर ज़ोर देंगे। बेहतर सरकार–नागरिक सम्पर्क सुनिश्चित करने तथा बाधाओं एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शासन में प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया जाएगा।

बाह्य परिवेश में परिवर्तन

4. जैसाकि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय राजनैतिक परिवेश में बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने आर्थिक परिवेश में ऊर्जा का संचार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूप, जहां विश्वभर की आर्थिक वृद्धि में कमी के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, वहीं भारत की विकास संभावनाओं के पूर्वानुमान अधिक सकारात्मक हो गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और वर्ष 2015–16 में देश का सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक रूप से 8 से 8.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

5. माननीय प्रधानमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व में भारत ने अपने पड़ोसियों तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ वार्ता स्थापित करने में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इससे देश के लिए व्यापार एवं निवेश के अवसर खुले हैं। भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना से राज्यों के लिए विकास की योजना को और अधिक सकारात्मक आयाम मिले हैं। सहकारी संघवाद के लिए और राज्यों को विकास की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में यह एक सकारात्मक एवं अनन्य कदम है। केन्द्र सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने से इसे और मजबूती मिली है। इन सिफारिशों से, राज्यों को केन्द्रीय कर संसाधनों का हस्तांतरण 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। निःसन्देह यह लचीलापन हमारे लिए इन बढ़े हुए मुक्त संसाधनों के ईष्टतम उपयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है।

6. अब हम हमारे देश के निर्णायक मोड़ की दहलीज पर खड़े हैं, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस महान राष्ट्र की नई पीढ़ी के सपनों एवं आकांक्षाओं को साकार करने के लिए भारत को विकास एवं उन्नति के नये शिखर पर ले जाना चाहते हैं। हरियाणा में हमें अपने विकास के प्रयासों एवं आर्थिक नीतियों को माननीय प्रधानमंत्री के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने की जरूरत है। 'टीम इंडिया' में एक महत्वपूर्ण स्थान लेकर हरियाणा को भारत की नई विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

7. लम्बे विचार–विमर्श के उपरांत केन्द्र सरकार और राज्य वर्ष 2016–17 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने पर सहमत हो गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह एक आधुनिक, कुशल एवं व्यापक कर व्यवस्था की संभावना का संकेत देता है। इस मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों से हम पूरी तरह से सचेत हैं और वस्तु एवं सेवाओं के कराधान में नए युग के लिए प्रशासनिक व्यवस्था व प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं।

प्रमुख चुनौतियां

8. बजट प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व, मैं उन चुनौतियों को उजागर करना चाहूँगा, जिनसे आज हरियाणा जूझ रहा है। वर्षों से हमारी कृषि उत्पादकता स्थिर हो गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भी काफी नीचे चला गया है। कृषि से लाभ कम हुआ है तथा किसानों का कर्ज बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र में गेहूं–धान फसल चक्र प्रबलता से जारी है। हमारा कृषि उत्पाद विपणन भी केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के लिए खरीद पर निर्भर है। मृदा स्वास्थ्य और कृषि के लिए जल का उपयोग भी चिंता के प्रमुख विषय हैं। मौजूदा फसल पद्धति के संदर्भ में उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है। भू–जल के अत्यधिक दोहन से भू–जल संसाधन घटे हैं। इससे भू–जल के सतत् उपयोग की संभावनाओं पर संकट मंडरा रहा है। कृषि में पानी का न्यूनतम उपयोग, भू–जल पुनर्भरण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और विविधिकृत कृषि उत्पाद के लिए विश्वसनीय कृषि–विपणन सहायता समय की मांग है। गैर–परम्परागत फसलों के विपणन और उससे लाभ में निहित जोखिम के कारण फसल विविधिकरण के मुद्दे पर किसानों की आशंकाओं

को हमारी सरकार बखूबी समझती है। हम फसल विविधिकरण तथा सुनिश्चित एवं विश्वसनीय कृषि उत्पाद विपणन के लिए एक अनुकूल परिवेश बनाने और जल संरक्षण की विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

9. राज्य के विकास में क्षेत्रीय असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। राज्य संसाधनों के विषम आबंटन तथा असन्तुलित औद्योगिक निवेश, रोज़गार के असमान अवसरों और प्रतिव्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों से यह स्पष्ट है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों की कमी इससे संबंधित एक चुनौती है। राज्य में विनिर्माण आधार में स्थिरता ने इस समस्या को और विकट बना दिया है। अतः हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने के लिए निवेश आकर्षित करके तथा 'मेक इन इंडिया' और 'मेक इन हरियाणा' के लक्ष्य को हासिल करके औद्योगिक क्षेत्र और विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्योग को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है। हम विशेष रूप से रोजगार क्षमता, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा रोजगार सृजन पर ध्यान देंगे।

10. हमारा राज्य त्वरित शहरीकरण से गुज़र रहा है। ग्रामीण बेरोज़गारी के साथ बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन शहरों के आस–पास असंगठित विकास को बढ़ावा दे रहा है। हमारे शहरों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों के आस–पास नागरिक बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त तथा निम्न स्तर की हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन और रियल एस्टेट के विकास के लिए लाइसैंसिंग की नीतियां धरातल की जरूरतों को पूरा करने में असफल रही हैं। हमारी सरकार ग्रामीण रोजगार, उचित आवास और 'भूमि उपयोग परिवर्तन' नीतियों के लिए पहल करके तथा शहरी नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा कर इन मुद्दों का समाधान करेगी।

11. राज्य में पर्यावरण एक गम्भीर मुद्दा बन गया है। कृषि तथा उद्योग में विकास और शहरी प्रबंधन के हमारे वर्तमान प्रतिमानों ने जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ाया है। हमारी सरकार हमारी विकासात्मक जरूरतों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करेगी। शहरों के ठोस कचरे के निपटान के साथ–साथ उद्योगों एवं घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन सरकार के लिए प्राथमिकता के विषय रहेंगे। हम राज्य के सतत् विकास के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करने का प्रयास करेंगे।

12. अध्यक्ष महोदय, महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि "Knowing your self is the beginning of all wisdom" स्वयं को जानना ही बुद्धिमत्ता की शुरू है। महोदय, राज्य की वित्तीय स्थिति पर हाल ही में जारी श्वेत–पत्र राज्य के विकास के वर्तमान स्तर और वित्तीय स्थिति का आकलन करने तथा इसे चिह्नित करने का एक प्रयास था। इससे हरियाणा को आगे ले जाने में आने वाली चुनौतियों को समझने और तदनुसार उचित नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, श्वेत–पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि गत दशक खोए हुए अवसरों का ही दशक रहा। उभरती चुनौतियों का सामना करने में विफलता के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन को बढ़ावा मिला। इन कमजोरियों के बावजूद हम आने वाले दिनों में अपनी समृद्धि के प्रति आशावान हैं। हरियाणा को भू–रणनीतिक बढ़त हासिल है। हरियाणा के लोग उद्यमी और लगनशील हैं तथा हमारे युवाओं में विश्व विजेता बनने का आग्रह, कौशल और भावना है। प्रत्याशित राष्ट्रीय आर्थिक पुनरुत्थान हमारी सरकार

[कैप्टन अभिमन्यु]

और हरियाणा के लोगों के लिए एक और मौका है। हरियाणा के लोगों के प्रयास और सरकार की नीतिगत पहलों के तालमेल से हम विकास की गति को बढ़ाने तथा समृद्धि की ओर लम्बे डग भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अतः, मुझे विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में हरियाणा सही मायनों में दोहरे अंकों में वृद्धि हासिल कर सकता है।

व्यापक आर्थिक संकेतक एवं दृष्टिकोण

13. किसी शायर ने कहा है कि: माना कि अन्धेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जलाना कहाँ मना है

मुश्किलें तो आयेंगी, हौंसलों से रिश्ता रख,
मंजिलों को पाना है, तो रास्तों से रिश्ता रख।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर (2004–05) मूल्यों पर 8.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत रही। वर्ष 2012–13 और 2013–14 में राज्य की अर्थव्यवस्था क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वर्ष 2014–15 के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,15,146 करोड़ रुपये अनुमानित है, जोकि वर्ष 2013–14 की तुलना में स्थिर मूल्यों पर 7.8 प्रतिशत और चालू मूल्यों पर 11.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,35,310 करोड़ रुपये है।

14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उपरोक्त आंकड़ों के संदर्भ में, राज्य की प्रतिव्यक्ति आय चालू मूल्यों पर वर्ष 2013–14 के 1,33,427 रुपये की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान 1,47,076 रुपये अनुमानित है, जोकि 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर मूल्यों (2004–05) पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013–14 के 67,260 रुपये से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 71,493 रुपये हो गई है, जोकि 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

15. राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक संघटन में पूर्ववर्ती रुझान जारी रहा। वर्ष 2013–14 के दौरान स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 15.3 प्रतिशत था। द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 27.7 प्रतिशत और 57 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14.2 प्रतिशत और 30,504 करोड़ रुपये तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 26.9 प्रतिशत एवं 57,936 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2014–15 के दौरान तृतीयक क्षेत्र का योगदान 58.9 प्रतिशत और 1,26,706 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में 0.1 प्रतिशत की मामूली कमी आई है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

16. नीति आयोग के विचार–विमर्श के दौरान सरकारी खर्च को योजनागत एवं गैर–योजनागत रूप में वर्गीकृत करने की परम्परागत विधि पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया गया है। खर्चों का योजनागत एवं गैर–योजनागत वर्गीकरण कृत्रिम है क्योंकि यह किसी क्षेत्र में सकल

सार्वजनिक निवेश को प्रतिबिम्बित नहीं करता, बल्कि वृद्धिशील खर्च पर बल देता है। बहरहाल, चूंकि इस मुद्दे पर अभी एक राष्ट्रीय सहमति बननी है, इसलिए हमने बजट अनुमान 2015–16 में योजनागत एवं गैर–योजनागत खर्च के परम्परागत वर्गीकरण को कायम रखा है।

माननीय अध्यक्ष जी, आगे वार्षिक योजना शुरू करने से पूर्व आपके माध्यम से कुछ सूचना वित्त विभाग ने सभी सभासदों को सील बन्द पैकेट्स में हार्ड कॉपी के रूप में एक नजर में बजट और बजट भाषण 2015-16 के साथ डिजिटल फॉरमेट में कॉम्पैक्टडे सी.डी. पर बजट दस्तावेज प्रदान किए हैं। कॉम्पैक्टडे सी.डी. में निम्न बजट दस्तावेज शामिल है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत अनुमान बजट 2015-16 खण्ड-1। खर्च का विस्तृत अनुमान बजट 2015-16 खण्ड-2, योजनागत स्कीमों का विस्तृत अनुमान बजट 2015-16 खण्ड-3, वार्षिक वित्तीय विवरण और व्याख्यात्मक ज्ञापन बजट 2015-16, व्याख्यात्मक ज्ञापन योजनागत स्कीम बजट 2015-16, हरियाणा राज कोषिय उत्तर.दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन यथाअपेक्षित राज कोषिय नीति का विवरण, स्थानीय निकायों को बजट हस्तान्तरण 2015-16 आर्थिक सर्वे हरियाणा 2014-15, सांख्यिकीय सारांश 2013-14। जैसा कि माननीय सभासद जानते हैं कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों को बजट भाषण में शामिल नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दस्तावेज के विस्तृत विवरण कम्प्यूटर पर देखे जा सकते है।

वार्षिक योजना 2015–16

17. मैं वार्षिक योजना 2015–16 के लिए 25,743.46 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,106.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। यह वर्ष 2014–15 के लिए 22,109.57 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों पर 16.44 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में विकास गतिविधियों पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 7,467.50 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों द्वारा 798.39 करोड़ रुपये का गैर–बजट परिव्यय किया जाएगा।

18. वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां 45,419.14 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं, जिसमें 33,402.75 करोड़ रुपये का राज्य का अपना कर राजस्व और 12,016.39 करोड़ रुपये का गैर–कर राजस्व शामिल है। बजट अनुमान 2015–16 के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां 52,312.10 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 38,929.40 करोड़ रुपये का राज्य का अपना कर राजस्व और 13,382.70 करोड़ रुपये का गैर–कर राजस्व अनुमानित है, जोकि वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों पर 15.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। संशोधित अनुमान, 2014–15 के लिए, राजस्व परिव्यय 54,919.10 करोड़ रुपये तथा बजट अनुमान, 2015–16 में 61,869.62 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैं, जोकि 12.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें से 17,060.56 करोड़ रुपये वेतनों पर, 5,900 करोड़ रुपये पैंशनों पर और 8,563.75 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी पर खर्च किए जाएंगे। संशोधित अनुमान, 2014–15 में पूंजीगत व्यय 6,530.72 करोड़ रुपये अनुमानित है और बजट अनुमान, 2015–16 के लिए 7,270.67 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैं। संशोधित अनुमान, 2014–15 में राजस्व घाटा 9,499.98 करोड़ रुपये और बजट अनुमान, 2015–16 में 9,557.52 करोड़ रुपये प्रक्षेपित

[कैप्टन अभिमन्यु]

है। संशोधित अनुमान, 2014–15 में 15,628.92 करोड़ रुपये और बजट अनुमान, 2015–16 में 16,423.58 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा प्रक्षेपित है।

19. महोदय, वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों में न तो नये कर लगाने और न ही वर्तमान कर दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है। मैं जैव उर्वरकों पर वैट हटाने का प्रस्ताव करता हूँ क्योंकि पर्यावरण एवं मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती और जैव उर्वरकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारी विकासात्मक रणनीति के संदर्भ में एलइडी लाइटों और पाइप फिटिंग एवं प्री0 फेब स्टील स्ट्रक्चर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इन पर वैट की दर को कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन छूटों के बावजूद सरलीकृत क्रियान्वयन एवं बेहतर अनुपालन के कारण वर्ष 2015–16 में हम अपनी कर प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।

20. हरियाणा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्ष 2011–12 और 2010–11 तक क्रमशः राजस्व घाटे को खत्म करने और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य था। बहरहाल, ये राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। संशोधित अनुमान, 2014–15 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 2.10 प्रतिशत और बजट अनुमान, 2015–16 में लगभग 1.83 प्रतिशत रहा। संशोधित अनुमान, 2014–15 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत और बजट अनुमान, 2015–16 में 3.14 प्रतिशत रहने की संभावना है। हमारी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति का यह पहलू चिंता का विषय है। विकास अनुमानों और ऋण चुकाने की अपनी क्षमता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत हरियाणा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत आगामी 5 वर्षों के लिए नये लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। हम विकास, राजस्व एवं राजकोषीय प्रबंधन के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को निश्चित तौर पर ध्यान में रखेंगे। 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान चालू मूल्य पर राज्य की औसत वार्षिक विकास दर 15.73 प्रतिशत अनुमानित की है। उनके अनुसार वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2015–16 से राज्य की निवल ऋण सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.25 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की गई है।

21. अक्तूबर, 2014 में हमारी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से हम विभिन्न वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हमने अनेक वर्तमान कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किए हैं और नये कार्यक्रम एवं नीतियां लागू की हैं। 9 मार्च, 2015 को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने इस गरिमामय सदन को संबोधित किया। उनका अभिभाषण विभिन्न क्षेत्रों एवं विभागों के लिए हमारी सरकार के दृष्टिकोण का विवरण है। इस अभिभाषण में पहले घोषित एवं प्रक्रियाधीन विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं पहलों के तर्कसंगत विवरण और वांछित प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत यह बजट इन बताई गई प्राथमिकताओं के अनुसार वित्तीय संसाधनों को जुटाने का एक प्रयास है। अतः मैं

इन नीतियों एवं कार्यक्रमों को पुनः न दोहराते हुए बजट अनुमान, 2015–16 के लिए क्षेत्रवार एवं विभागवार आबंटनों की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

देश के महान कृषक नेता दीनबंधु सर छोटू राम का दृढ़ विश्वास था कि राज्य के समस्त आर्थिक व सामाजिक जीवन की धुरी व केन्द्र कृषक व कृषि हैं। अतः सभी सत्तासीनों के हृदय में कृषक के लिए प्रमुख स्थान होना चाहिए। यदि कृषक समृद्ध है तो सभी समृद्ध होंगे। किंतु यदि कृषक की दुर्दशा है तो निश्चित रूप से सबके दुर्दिन होंगे। इस सूत्र वाक्य से प्रेरित होकर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए मैं निम्न प्रस्ताव करता हूँ।

22. इस क्षेत्र में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं सहकारिता विभाग शामिल हैं। मैं इस क्षेत्र के लिये 2,636.65 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 10.10 प्रतिशत अधिक है।

23. इस प्रस्तावित आबंटन का विभागवार विवरण इस प्रकार है। कृषि एवं बागवानी विभागों के लिए मैं 1257.17 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। यह परिव्यय संशोधित अनुमान, 2014–15 से 20.88 प्रतिशत अधिक है। मत्स्य विभाग के लिए मैं 48.43 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 16.15 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है जो कि वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 132.71 प्रतिशत अधिक है। पशुपालन एवं डेयरी विभागों के लिए मैं 686.18 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करता हूँ, जिसमें 191.30 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 27.87 प्रतिशत अधिक है।

24. हमारी सरकार ने कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनेक नई पहल की हैं। गायों की देसी नस्लों के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए 'गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसानों को विपणन के लिए एक ब्रांड उपलब्ध करने के लिए 'लघु, कृषक कृषि व्यापार संघ' के पास 'हरियाणा फ्रैश' के नाम से एक नया ब्रांड पंजीकृत करवाया गया है। 'अटल खेती बाड़ी खाता योजना' के तहत किसानों को प्रदान किए जा रहे डिजिटल पंजीकरण कार्ड में किसानों की कृषि गतिविधियों से संबंधित सभी प्रासंगिक डाटा का रिकार्ड होगा तथा ये ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। कृषि विपणन को सुदृढ़ करने के लिए बहुउद्देशीय समितियों जैसेकि फल एवं सब्जी समितियां, सेवा समितियां, सहकारी गऊशाला आदि का पंजीकरण करके सहकारी समितियों में महिलाओं एवं युवाओं को शामिल किया जाएगा। किसानों को मौजूदा गेहूं–धान के फसल चक्र से निकल कर कपास, तिलहनों, दालों, मक्का, औषधीय पौधों, फूलों और बागवानी फसलों जैसी नकदी फसलों के माध्यम से फसल विविधिकरण के लिए प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जा रहा है। भारत सरकार की 'परम्परागत कृषि विकास योजना' को आगामी वित्त वर्ष से राज्य में शुरू किया जाएगा। अधिकतर चैनलों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'हर खेत को पानी' के लक्ष्य के साथ आगामी 6 महीनों में विशेष प्रयास किए जाएंगे। पशुचिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के एक नये परिसर का निर्माण किया जाएगा।

[कैप्टन अभिमन्यु]

आर्थिक आधारभूत संरचना क्षेत्र

25. आर्थिक आधारभूत संरचना क्षेत्र में बिजली, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण(भवन एवं सडकें), जल संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग शामिल हैं। मैं इस क्षेत्र के लिए 17,331.08 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 5,793.65 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 7.56 प्रतिशत अधिक है।

26. इस प्रस्तावित आबंटन का विभागवार विवरण इस प्रकार है। बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभागों के लिए मैं बजट अनुमान, 2015–16 में 6546.91 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 917.50 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन शामिल है। यह योजनागत आबंटन वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 45.25 प्रतिशत अधिक है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए मैं बजट अनुमान, 2015–16 में 2,671.55 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 1150 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 3.43 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान 2015–16 में लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के लिए मैं 3291.76 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 2,281.25 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन और 1,010.51 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत आबंटन शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 6.57 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर–योजनागत परिव्यय में 11.78 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें सड़कों और सरकारी भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव जैसे खर्च शामिल हैं। बजट अनुमान, 2015–16 में उद्योग एवं वाणिज्य और खान एवं भू–विज्ञान के लिए मैं 219.74 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ, जिसमें 174.17 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन शामिल है। जहां, वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल परिव्यय 25.60 प्रतिशत अधिक है, वहीं विभाग के योजनागत परिव्यय को वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 29.47 प्रतिशत बढ़ाया गया है। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभागों के लिए मैं बजट अनुमान, 2015–16 में 2249.38 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 197 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन और 2052.38 करोड़ रुपये का गैर– योजनागत आबंटन शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 13.71 प्रतिशत अधिक है। सिंचाई एवं जल संसाधनों के लिए मैं बजट अनुमान, 2015–16 में 2,351.74 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 1073.73 करोड़ रुपये का योजनागत और 1,278.01 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत आबंटन शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 6.45 प्रतिशत अधिक है।

27. हमारी सरकार प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र और 'व्यापार की सहूलियत' पर विशेष बल देते हुए नई उद्योग नीति–2015 बना रही है। हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रैस–वे का कार्य फिर से शुरू करवाने की पहल की है। सतलुज–यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य शीघ्र करवाना तथा बी.एम.एल.–हांसी ब्रांच–बुटाना ब्रांच बहुउद्देशीय

लिंक चैनल को जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं कि हरियाणा को सभी अन्तर्राज्यीय नदी–जल समझौतों से अपने हिस्से का पानी मिले। लखवार परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होने की संभावना है तथा व्यासी परियोजना के कार्य में प्रगति हो रही है। सरकार आगामी वर्ष में जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के पम्प घरों की उठान क्षमता और चैनलों की प्रवाह क्षमता को सुधारने की एक मुख्य परियोजना पर भी कार्य शुरू करेगी। हमने बिजली आपूर्ति को और बढ़ाने तथा पुरानी और अक्षम इकाइयों को बंद करके इनके स्थान पर पानीपत में लगभग चार हजार करोड़ रुपये की लागत से 800 मैगावाट का एक सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। यमुना नदी के साथ लगते 28 शहरों में वर्तमान सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और नये सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित करने की एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके मार्च, 2017 तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है। इसी प्रकार, घग्गर नदी के साथ लगते 18 कस्बों में वर्तमान सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के संवर्धन एवं नये सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके दिसम्बर, 2016 तक पूरा होने की सम्भावना है। सरकार हरियाणा में अंदरूनी राज्य मार्गों पर निजी संचालकों को परमिट देने के लिए एक नई स्टेज कैरिज परमिट स्कीम तैयार कर रही है। द्वारका (दिल्ली) और इफको चौक, गुड़गांव के बीच मैट्रो लिंक वर्ष, 2015 में चालू हो सकेगी, जबकि बहादुरगढ़ को अप्रैल, 2016 तक दिल्ली से मैट्रो द्वारा जोड़े जाने की संभावना है।

सामाजिक क्षेत्र

28. सामाजिक व राजनीतिक जीवन में हमारे प्रेरणा स्रोत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें कतार में अंतिम व्यक्ति की भलाई व प्रगति (अंत्योदय) के प्रति सचेत किया है। पण्डित उपाध्याय का समाज के शोषित, पीड़ित व वंचित बच्चों, वृद्धों व असहाय व्यक्तियों की सहायता का आह्वान हमें अपना कर्तव्य बोध कराता रहेगा। सामाजिक क्षेत्र के लिए वर्ष 2015–16 के लिए मैं निम्न प्रावधान करता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा–शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम एवं रोजगार विभाग शामिल हैं। मैं इस क्षेत्र के लिए 27,291.27 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 17,160.62 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह परिव्यय मौजूदा वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 16.93 प्रतिशत अधिक है।

29. इस प्रस्तावित आबंटन का विभागवार विवरण इस प्रकार है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मैं 3,028.61 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 1,845.88 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 14.45 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान, 2015–16 में शिक्षा के लिए मैं 11,615.70 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 4,463.64 करोड़ रुपये का योजनागत और 7,152.06 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत बजट शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 12.91 प्रतिशत अधिक है। गैर–योजनागत बजट में 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए मैं 1193.29 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 976.33 करोड़

[कैप्टन अभिमन्यु]

रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 8.83 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान, 2015–16 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए मैं 368.79 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 213.03 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 6.73 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए मैं 3,641.27 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 3,603.86 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 22.20 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान, 2015–16 में विकास एवं पंचायत विभाग के लिए मैं 2,734.71 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 2,007.96 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 26.52 प्रतिशत अधिक है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए मैं 2215.98 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 2,006.79 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 17.26 प्रतिशत अधिक है। श्रम एवं रोज़गार विभागों के लिए मैं 136.32 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 15.33 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 20.38 प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए मैं 371.66 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 266.42 करोड़ रुपये का योजनागत और 105.24 करोड़ रुपये का गैर–योजनागत परिव्यय शामिल है। गैर–योजनागत आबंटन में 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.88 प्रतिशत की वृद्धि है। तकनीकी शिक्षा के लिए मैं 544.72 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर रहा हूँ। इसमें 421.51 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों से 48.66 प्रतिशत अधिक है।

30. सामाजिक क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। राज्य सरकार ने बालिकाओं के संरक्षण और समाज में उनका उचित हक दिलाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ आशा प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना और कन्या कोष योजना शुरू की है। 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों, टपरीवास जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को लड़की की शादी पर 41,000 रुपये तक दिये जाएंगे। सरकार का अन्तार्जातीय विवाह योजना के तहत प्रत्येक दम्पति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण युवाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाने के मद्देनजर 'गर्वित–ग्रामीण विकास के लिए तरुण' नामक एक नई मार्गदर्शक योजना शुरू की गई है। एक नई योजना के तहत ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं। गांवों में एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए 'स्वच्छ हरियाणा–स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया गया है। विधायकों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा संगठनों की सक्रिय भागीदारी से गांवों का तेजी से सर्वांगीण विकास करने के लिए 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' और 'स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना' शुरू की गई है।

31. राज्य सरकार ने युवाओं के कल्याण और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वस्थता नीति–2015 लागू की है। पंचायत एवं खंड स्तर पर 'योग एवं व्यायामशाला' नामक एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार चिकित्सा की हमारी प्राचीन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयुष चिकित्सा पद्धति पर विशेष बल देने की इच्छुक है। राज्य सरकार ने करनाल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केन्द्र के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने आगामी वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दो रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर गेहूं के अतिरिक्त एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा एवं मक्का की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा भत्तों की दर में 200 रुपये की वृद्धि की है और जनवरी, 2015 से सभी लाभानुभोगियों को 1200 रुपये प्रतिमास दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा की आप जानते हैं, हरियाणा हमारी प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। इसके पुरातात्विक अवशेष एवं प्रतिकृतियां अपार सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की हैं। हमारी सरकार ने कुरूक्षेत्र में राज्य संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया है और वर्ष 2015–16 में इसके लिए मैं 20 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ। हमने सरस्वती नदी के अनुसंधान, पुनरुद्धार व प्रचार के लिए सरस्वती हैरीटेज विकास बोर्ड की स्थापना की है।

तृतीय स्तम्भ को सशक्त बनाना

32. चौथे राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 30 जून, 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। जिस समय चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई उस समय वित्त आयोग की अवधि के लिए केवल एक वित्त वर्ष (2015–16) ही बचा था। इसलिए चौथे राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करने के लिए केबिनेट उप–समिति गठित करने की आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करने और फिर उसके निर्णयों को 2015–16 में बजट अनुमानों के रूप में शामिल करने का समय नहीं बचा था। अतः हम वर्ष 2015–16 में तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित वर्तमान हस्तांतरण पद्धति को जारी रखेंगे। इस रूपरेखा के तहत वर्ष 2014–15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 419.35 करोड़ रुपये और बजट अनुमान, 2015–16 में 548.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वैट पर सरचार्ज, स्टाम्प शुल्क और मुआवजा अदायगी आदि के रूप में वर्ष 2014–15 में 1,933.08 करोड़ रुपये और बजट अनुमान, 2015–16 में 2,221.77 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण के अलावा आबंटित किए गए हैं। हमारी सरकार वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए हस्तांतरण पद्धति की सिफारिश करने के लिए शीघ्र ही पांचवां राज्य वित्त आयोग गठित करेगी।

*12.00 बजे

ई–शासन, प्रभावी शासन

33. हरियाणा में विकास एवं कल्याण का सूत्रपात करने की हमारी सरकार की मंशा उक्त वर्णित कार्यक्रमों एवं नीतियों से प्रतिबिम्बित होती है। इन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित एवं निष्पादित करके ही इनके वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हम 'सरकार कम से कम–सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। हम राज्य नौकरशाही को सक्षम एवं प्रभावी, उत्तरदायी एवं सक्रिय बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। लोगों की सुशासन की इच्छा

[कैप्टन अभिमन्यु]

को पूरा करने के लिए हम सरकार के सेवा प्रदायगी तंत्र में आवश्यक परिवर्तन लाएंगे। सरकार कर्मचारियों को आम नागरिकों के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने और सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा, सूचना प्रौद्यागिकी एवं ई–शासन के उपयोग से प्रशासनिक प्रणाली को व्यापक रूप से गुणवत्तापरक बनाया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विभागों में ई–शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गये हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर, 2014 को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया गया था। इस अवसर पर लोगों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए 'सीएम विंडो' वैब पोर्टल शुरू किया गया है। पुलिस विभाग के नागरिक पोर्टल 'इरसमय' के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्ष 2015–16 में एक व्यापक ई–सक्षम अस्पताल प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन के लिए 'शुरू से अंत तक' ई–समाधान की योजना बनाई गई है। कराधान विभाग करदाताओं के साथ ऑन लाइन सम्पर्क के लिए एक व्यापक आईटी–सक्षम प्रणाली विकसित कर रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए आबकारी ठेकों की नीलामी ई–निविदा के माध्यम से की जा रही है। वर्ष 2015–16 में लगभग 150 वैब आधारित नागरिक सेवाएं शुरू की जाएंगी। एक नई योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्राम सचिवालय भी ग्राम परिसम्पत्तियों और पंचायत खातों के रखरखाव और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन के लिए भी ई–सक्षम होंगे। सम्पत्ति पंजीकरण को सरल करने के लिए कागजी स्टाम्प पेपर के एवज में ई–स्टैम्पिंग प्रणाली शुरू की जा रही है।

34. हमारी सरकार विभिन्न विभागों के ई–शासन आवेदनों को जोड़ने और आंकड़ों के अभिसरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस बनाने की योजना बना रही है। इससे बेहतर नागरिक सेवा मानचित्रण और समेकित कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नैटवर्क सिस्टम के तहत नागरिकों को डिजिटल अवसंरचना के लाभ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत सितम्बर, 2015 तक हरियाणा के लगभग 4000 गांवों को 100 एम.बी.पी.एस. इंटरनैट कनैक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये ई–शासन की पहल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक उचित आधार प्रदान करेंगे। यह सरकार को चुस्त, पारदर्शी बनाने के साथ कार्य को आसान और भ्रष्टाचार–मुक्त बनाएगी।

बजट अनुमान, 2015–16

35. महोदय, मैं गर्व के साथ ऐतरेय ब्राह्मण से एक श्लोक उद्धृत करता हूँ। 'अस्मिन् राष्ट्रे आवेशयामि'। इसका अर्थ है कि मैं इस राज्य के सम्पत्ति सृजन के लिए योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ।

36. महोदय, बजट अनुमान, 2015–16 के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) 68,985.87 करोड़ रुपये दर्शायी गई हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 52,312.10 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक ऋण का निवल) 16,673.77 करोड़ रुपये की हैं। ये प्राप्तियां 12,887.81 करोड़ रुपये बढ़कर 2014–15 के संशोधन अनुमानों की तुलना में 22.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इसमें 2014–15 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 15.18 प्रतिशत की दर से 6,892.96 करोड़ रुपये की वृद्धि और 5,984.85 करोड़ रुपये की वृद्धि पूंजीगत प्राप्तियों में दर्शायी गई है जो 55.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों के तहत कुल खर्च (पुनर्भुगतानों को छोड़कर) 69,140.29 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जिसमें से राजस्व खर्च 61,869.62 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 7,270.67 करोड़ रुपये है। 2014–15 के संशोधित अनुमानों के कुल खर्च की तुलना में यह 7,690.47 करोड़ रुपये और 12.52 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से राजस्व खर्च में 6,950.52 करोड़ रुपये और 12.66 प्रतिशत की वृद्धि होगी और पूंजीगत खर्च में 739.95 करोड़ रुपये और 11.33 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

37. महोदय, अब मैं वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमानों में क्षेत्रवार आबंटनों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। सहकारिता सहित कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को 2,636.66 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, बिजली क्षेत्र को 6,546.91 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं, सड़क एवं परिवहन क्षेत्र को 5,541.14 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, सिंचाई क्षेत्र को 2,351.74 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र को 2,671.55 करोड़ रुपये मिलेंगे, शहरी विकास क्षेत्र को 3,409.37 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति विभागों को 11,907.09 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा को 916.38 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को 3,028.61 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण समेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को 5,295.11 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 2,734.71 करोड़ रुपये मिलेंगे।

38. महोदय, यह बजट प्रस्ताव 'सबका साथ–सबका विकास' के सिद्धान्त पर प्रस्तुत किया गया है। यह पूंजीगत खर्च और अवसंरचना विकास पर विशेष बल देता है। इसमें कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। यह सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के बीच असमानता को दुरुस्त करता है। यह कल्याणकारी राज्य की हमारी वचनबद्धता को दोहराते हुये सामाजिक क्षेत्र पर और अधिक बल देता है। मैं इस सम्मानित सदन से, राजनैतिक एवं वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर इस पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने तथा इस प्रस्ताव को अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ। मैं एक विकसित और प्रगतिशील हरियाणा के लिए मिलकर कार्य करने की भी अपील करता हूँ।

39. महोदय, पहली नवम्बर, 2015 को हरियाणा राज्य अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश करेगा। यह प्रदेशवासियों और इस सदन में हम सब के लिए एक ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अवसर है कि हम हरियाणा की स्थापना में योगदान करने वाले सभी महानुभावों का सम्मानपूर्वक स्मरण करें। आइए, हम सब राज्य निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने का संकल्प लें और हरियाणा का सही मायनों में वैश्विक मानकों के अनुरूप विकास करें।

महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों को इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। वंदे मातरम! जय हिन्द!

श्री अध्यक्ष : अब सभा बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 को प्रात: 10:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*12.04 बजे (तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 को प्रात: 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित की गई।)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh LIBRARY

53380—H.V.S.—H.G.P.,Chd.